THE UNION BUDGET, 2017-18 — *Contd.

श्री शंकरभाई एन. वेगड़ (गुजरात): डिप्टी चेयरमैन साहब, आपने मुझे जनरल बजट पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं। मैं तहेदिल से इस बजट का स्वागत करता हूं और हमारे प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र भाई मोदी जी और वित्त मंत्री श्री अरुण जेटली जी को बधाई देता हूं।

सर, पिछले साल हर गांव को, हर घर को अच्छी तरह से बिजली मिले, इसके लिए आयोजन किया गया था। इस साल "पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना" के अंतर्गत 4,814 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। हिन्दुस्तान के आज़ाद होने के बाद आज तक 18,000 से ज्यादा गांवों में बिजली नहीं पहुंच पायी है। सरकार ने 12,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का आयोजन किया है और सन् 2019 तक हिन्दुस्तान के हर गांव में बिजली पहुंचाई जाए, ऐसा हमारे वित्त मंत्री और प्रधान मंत्री जी ने आयोजन किया है, जो एक सराहनीय कदम है। इसी तरह से "उजाला योजना" के अंतर्गत बिजली की बचत हो और सस्ते दाम पर बिजली के बल्ब्स, पंखे और ट्यूबलाइट्स मिलें, इसके लिए भी इस बजट में आयोजन किया गया है। हर गांव को पीने का शुद्ध पानी मिले, इसके लिए भी इस साल 6,050 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। हर गांव को अच्छा रास्ता मिले, अच्छी सड़कें मिलें, ताकि गांव वाले भी शहर में अपना business करने के लिए आ सकें, उनको गांव से शहर आने-जाने की अच्छी सुविधाएं मिलें, इसके लिए "प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना" के अंतर्गत 19,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। इसी प्रकार "प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना" है। अब तक पिछली सरकार ने बीमा योजनाएं लागू की थीं, लेकिन इस योजना में ऐसा प्रावधान किया गया है कि किसान जब बीज बोता है और अगर उसका बीज फेल हो जाता है तो इस बीमा योजना में प्रावधान होने के कारण उसको उसके नुकसान की भरपाई की जाती है। पहले तहसील गिना जाता था, इस फसल बीमा योजना में अब गांव आते हैं और गांव में भी मान लीजिए एक साइड बारिश ज्यादा होती है और दूसरी साइड कम बारिश होती है और बहुत अधिक बारिश या सूखे के कारण 10-15 किसानों को नुकसान हो जाता है, तो उसके लिए भी प्रावधान किया गया है कि उन 10-15 किसानों को भी नुकसान की भरपाई की जाएगी। हर किसान को फसल के ऊपर अच्छी तरह से ऋण मिले, इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" के अंतर्गत हर खेत को कृषि के लिए पानी मिले, इसका प्रबंध किया गया है - खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में।

इसी तरह से जब हम हर साल bore well से सिंचाई करते हैं तो जमीन के नीचे पानी का स्तर बहुत नीचे चला जाता है। हम अगर ज़मीन से पानी निकालते रहेंगे तो कब तक चलेगा? एक दिन ऐसा आएगा कि भूतल में पानी खत्म हो जाएगा। इसलिए "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" है कि बारिश का पानी जमीन में कैसे उतरे, इसके लिए भी इस बजट में आबंटन किया गया है। "प्रधान मंत्री कृषि सिंचाई योजना" के तहत 7,347 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया है। हर खेत में soil की क्वॉलिटी क्या है - मनुष्य के शरीर की जो जांच होती है कि उसके शरीर में क्या कमियां हैं, उनकी पूर्ति के लिए हम ध्यान देते हैं, लेकिन हमारा भारत कृषि प्रधान देश है, उसके खेत में क्या कमी है, आज तक किसी

*Further discussion continued from 9.2.17.

ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया था, लेकिन यह सरकार "Soil Health Card" की योजना लेकर आयी, जिसके अंतर्गत हर खेत की जांच की जाएगी कि खेत में क्या कमी है, किस तत्व की कमी है, ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा खाद मिले या अगर और किसी चीज़ की कमी है तो उसकी पूर्ति की जाए। इसके अतिरिक्त उसके खेत में क्या बोया जाए, ताकि उसकी पैदावार बढ़ सके। इस प्रकार 'Soil Health Card' की योजना लाकर इस सरकार ने बहुत सराहनीय काम किया है।

इसके अतिरिक्त मैं organic खेती की बात करना चाहता हूं। इस बजट में organic खेती के लिए कुछ रकम दी गयी है। सर, organic खेती करते समय खेत में जो बीज बोया जाता है, वह organic होता है। Organic खेती करते समय खेत में किसी तरह की रासायनिक खाद या fertilizer का प्रयोग नहीं किया जाता है। हिन्दुस्तान का स्वास्थ्य ठीक रहे, इसके लिए हमारे हिन्दुस्तान के हर गांव को organic खेती करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि organic खेती के लिए इस सरकार ने जो प्रावधान किया है, वह बहुत सराहनीय है। ऑर्गेनिक खेती के लिए ऑर्गेनिक खाद भी चाहिए। उस ऑर्गेनिक खाद के लिए हमारे यहां गाय, भैंस, बैल होने चाहिए। इस सदन में शर्म के मारे मुझे नहीं बोलना चाहिए, फिर भी मैं बोलता हूं कि गाय को काटने की बात करने वाले सदस्य भी इस सदन में मौजूद हैं। अरे, गाय नहीं बचेगी, तो हिन्दुस्तान को बचाने वाला कोई नहीं रहेगा। गाय बचेगी, तो हिन्दुस्तान बचेगा। गाय के गोबर में और गाय के मूत्र में इतनी ताकत है कि इस आधुनिक युग में जो कैंसर होता है, इसको मिटाने की कोई दवा सुझाई नहीं गई है, लेकिन गाय के गोबर और गौमूत्र में इतनी ताकत है कि यदि सही ढंग से इसका उपयोग किया जाए, तो 100 परसेंट कैंसर मिट जाता है। जिसके आंगन में गाय बंधी रहती है, उसमें इतनी शक्ति होती है कि रोग के जो जंतु अगल-बगल में होते हैं, वे नष्ट हो जाते हैं। गाय के कारण उस परिवार में कोई आदमी बीमार नहीं होता है। यह इसका लाभ है, इसलिए मैं अपनी ओर से सभी सांसदों से अनुरोध करता हूं कि हम सभी को गाय को बचाना चाहिए।

स्वस्थ्य भारत बने, स्वस्थता में प्रभु का वास है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी लिखा गया है, वेदों में भी कहा गया है। गांधी जी भी कहते थे कि स्वस्थता में प्रभु का वास है। इसलिए स्वस्थता के लिए 16,248 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा जन-धन योजना है। आज तकरीबन 23 करोड़ लोगों के जन-धन योजना के अकाउंट खुल गए हैं। इसके कारण सामान्य आदमी को, चाहे केन्द्र सरकार की योजना हो या राज्य सरकार की योजना हो, उस योजना का सीधा लाभ मिल रहा है। जो गैस सब्सिडी मिलती है, उसका लाभ सीधे लोगों के बैंक अकाउंट में चला जाता है। किसी के हाथ में पैसा नहीं जाता है, इसलिए भ्रष्टाचार कम हुआ है। एक समय ऐसा था जब हमारे पंथ प्रधान भी कह चुके थे कि हम दिल्ली से एक रुपया गरीब के लिए भेजते हैं, लेकिन गरीब के पास पहुंचते-पहुंचते सिर्फ 15 पैसा रहा जाता है और 85 पैसा बीच में खाया जाता था, वह भ्रष्टाचार में चला जाता था। जन-धन योजना के कारण अब गरीब का पैसा सीधे उसके अकाउंट में चला जाता है और उसके बिना कोई बैंक से पैसा निकाल भी नहीं सकता है। यह बहुत ही सराहनीय कार्य हमारे पंथ प्रधान और वित्त मंत्री जी ने किया है।

[श्री शंकरभाई एन. वेगड़]

सर, कौशल विकास योजना और मुद्रा बैंक योजना के माध्यम से हमारे बहुत से बेरोजगारों को रोजगार मिलना शुरू हो गया है। इस बजट में युवाओं को काफी तरजीह दी गई और उन्हें रोजगार के लिए तैयार करने और रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 4,000 करोड़ रुपए का संकल्प कार्यक्रम में पेश किया है। इसके तहत देश भर में साढ़े तीन करोड़ युवाओं को प्रशिक्षण उपलब्ध कराया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस वर्ष युवा और खेल मंत्रालय के बजट में कुल 335.11 करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी की गई है। इसके अलावा मुद्रा योजना के तहत कॉरपस फंड को 1.22 लाख करोड़ रुपये से दोगुना 2.44 लाख करोड़ रुपये किया गया है। इससे युवाओं को स्वरोजगार के जरिए लाभ होने की बात कही जा रही है।

आम बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री जी ने वर्ष 2017-18 में शिक्षा, कौशल और रोजगार के जरिए युवाओं में ऊर्जा भरने को 10 क्षेत्रों में से एक बताया है, जिस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार ने प्रधान मंत्री कौशल केन्द्र को मौजूदा 60 जिलों से बढ़ाकर देश भर में 600 से अधिक जिलों तक पहुंचाने का प्रस्ताव पेश किया है। इसके अलावा देश भर में 100 अंतर्राष्ट्रीय कौशल केन्द्र स्थापित किए जाएंगे, जहां पर उन्हें उन्नत प्रशिक्षण दिया जाएगा और उन्हें विदेशी भाषाओं के पाठ्यक्रमों की भी पेशकश की जाएगी। जेटली जी ने कहा है कि इससे देश के उन युवाओं को मदद मिलेगी, जो देश के बाहर नौकरी के अवसर चाहते हैं। इसके अलावा 2017-18 में 2,200 करोड़ रुपये की लागत से स्ट्राइव योजना का अगला चरण शुरू किया जाएगा, जिसमें आईटीआई में व्यावसायिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता सुधारी जाएगी और उद्योग संकुल दृष्टिकोण से प्रशिक्षु कार्यक्रम को मजबूत किया जाएगा।

मैं अब आवास योजना की बात करना चाहता हूं। महोदय, आवास योजना के लिए 29,033 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस के तहत अगले पांच वर्ष में देश के हर नागरिक के पास अपना घर होगा। वित्त मंत्री ने आम बजट में वर्ष 2022 तक देश के हर नागरिक को घर देने का वायदा किया है। इसके लिए आम बजट में सस्ती आवास योजना चलाने वाली कंपनियों के लिए मुनाफे से जुड़ी छूट को आकर्षक बनाया गया है। साथ ही अब तक 30 और 60 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र के बजाय 30 और 60 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र की गणना की जाएगी। 30 वर्ग मीटर की सीमा भी केवल चार मेट्रो शहरों की नगरपालिका सीमाओं के मामले में लागू होगी, जब कि मेट्रो के बाहरी क्षेत्र सहित देश के शेष सभी भागों के लिए 60 वर्ग मीटर की सीमा लागू होगी। इस योजना के तहत कार्य प्रारंभ होने के बाद भवन निर्माण की अवधि को पूरा करने की अवधि को मौजूदा तीन साल से बढ़ाकर पांच साल करने का भी प्रस्ताव किया गया है। राष्ट्रीय आवास बैंक वर्ष 2017-18 में 20 हजार करोड़ रुपए के होम लोन को पुनर्वित्त करेगा।

महोदय, मैं "मनरेगा" के संबंध में भी कुछ कहना चाहूंगा। "मनरेगा" में पहले बहुत भ्रष्टाचार हुआ है ...(**व्यवधान**)... अब तक क्या चल रहा था, यह पूरे देश को मालूम है। इस का नतीजा आपने यू.पी., महाराष्ट्र और दूसरी जगहों पर देख लिया है। "मनरेगा" में केन्द्र सरकार ने सभी आलोचनाओं

को खारिज करते हुए एक बार फिर "मनरेगा" पर भरोसा जताया है। विपक्ष ने रहते हुए भा.ज.पा. ने इस योजना की कड़ी आलोचना की थी, लेकिन 2017-18 के बजट में महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजार गारंटी योजना कानून के तहत अब तक के सर्वाधिक 48,000 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं। पिछले साल इसके लिए 38,500 करोड़ रुपए आबंटित किए गए थे। हालांकि पिछले साल के संशोधित बजट अनुमान में यह राशि 47,499 करोड़ रुपए हो गई थी। "मनरेगा" के तहत सौ दिन के रोजगार के अलावा आधारभूत ढांचे के निर्माण पर फोकस किया जाएगा, पांच लाख तालाब बनेंगे। वर्ष 2017-18 के दौरान खेतल से जुड़े पांच लाख तालाबों का काम शुरू किया जाएगा। यह पिछले पांच लाख तालाब और दस लाख कंपोस्ट खाद के गड्ढों के लक्ष्य के अलावा है। सरकार ने कहा है कि महिलाओं की भागीदारी 48 फीसदी से बढ़कर 55 फीसदी हो गयी है।

महोदय, स्वच्छ भारत मिशन में भारत ने एक बार फिर अपना फोकस जाहिर किया है। मिशन के तहत पिछले वर्ष की तुलना में करीब पांच हजार करोड़ रुपए का आबंटन बढ़ा है। बीते साल मिशन में 11,300 करोड़ रुपए दिए गए थे। अब यह राशि बढ़कर 16,248 करोड़ रुपए हो गयी है।

महोदय, महिला और बाल सशस्तीकरण के लिए भी इस बजट में ज्यादा-से-ज्यादा रकम आबंटित की गयी है। ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण बढ़ाने को ध्यान में रखते हुए बजट में गांव के स्तर पर महिला शक्ति केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव किया गया है। बजट में महिला और बाल कल्याण के लिए आबंटन 1,56,528 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 1,84,632 करोड़ रुपए करने का प्रस्ताव किया गया है। वित्त और कंपनी मामलों के मंत्री श्री अरुण जेटली ने आम बजट 2017-18 प्रस्तुत करते हुए कहा कि 14 लाख आईसीडीएस आंगनवाड़ी केन्द्रों में 500 करोड़ रुपए के आबंटन के साथ गांव के स्तर पर महिला शक्ति केन्द्र स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि यह ग्रामीण महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए कौशल विकास, रोजगार, डिजिटल साक्षरता, स्वास्थ्य और पोषण के अवसरों के लिए वन स्टॉप सामूहिक सहायता प्रदान करेंगे। श्री अरुण जेटली ने यह भी कहा कि गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने की राष्ट्रव्यापी योजना के अंतर्गत 6 हजार रुपए सीधे ऐसी गर्भवती महिला के बैंक खाते में जमा किए जाएंगे।

महोदय, एक भारत स्वस्थ भारत, एक भारत स्वच्छ भारत के सूत्र को सार्थक बनाने के लिए इस बजट में बहुत सारी योजनाओं में बहुत बड़ी रकम का आबंटन किया गया है। इसलिए मैं इस बजट का तहेदिल से स्वागत करता हूं और सपोर्ट करता हूं। धन्यवाद।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Thank you very much, Mr. Vegad. Now, Shri Naresh Agrawal.

श्री नरेश अग्रवाल (उत्तर प्रदेश): माननीय उपसभापति जी, माननीय नेता सदन कुछ अस्वस्थ हैं और आज सदन में उपस्थित नहीं हैं। हमारी कामना है कि वे जल्दी से स्वस्थ हों।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He is not well.

श्री नरेश अग्रवालः और जवाब भी वही दें तो ज्यादा अच्छा होगा। क्योंकिं सतोष जी को तो हम लोग उत्तर प्रदेश का मुख्य मंत्री मानकर चल रहे थे।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Nareshji, he has informed me. ...*(Interruptions)*... See, the Finance Minister has informed me ...*(Interruptions)*...

SHRI NARESH AGRAWAL: Sir, I am saying the same thing.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: He will come and reply.

SHRI NARESH AGRAWAL: Sir, I am saying the same thing that he is ill. I pray to God that he comes soon.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: And he will come for reply. The only thing is, not today.

श्री नरेश अग्रवालः यहां संतोष जी बैठे हुए हैं। हम लेग तो कुछ और समझ रहे थे। अब तो हमें भी ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Okay. Please.

श्री नरेश अग्रवालः अब तो हमें विश्वास होने लगा है कि भाग्य बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि जो सही है, उसके कहने में कभी हमें कोई परेशानी नहीं है। हमारे पूर्व मुख्य मंत्री ने दलीय सीमाओं से हटकर वहां पर भाग लिया, क्योंकि यह एक परम्परा है कि outgoing Chief Minister oath में जाता है, तो हम वहां गए। हम इन चीजों पर विश्वास नहीं करते हैं। यह तो छोटी मानसिकता ने पैदा कर दिया कि हम राजनीतिक दल एक दूसरे का विरोध मानने लगे हैं। श्रीमन्, विचारों का मतभेद होता था, कभी व्यक्तिगत मतभेद नहीं होता था। यह नहीं देखा जाता था कि हम किस दल में हैं और आप किस दल में हैं। हम सब संसद सदस्य हैं और हम सब जन प्रतिनिधि हैं और हम सबका अधिकार बराबर है, यह ठीक है कि हमारे विचार अलग हैं। मैं इसीलिए प्रधान मंत्री जी को बधाई देता हूं और यह कहना चाहता हूं कि जीत उनकी है, बीजेपी की नहीं है, वोट मोदी जी को दिया है, बीजेपी को नहीं दिया। मैं उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री जी को भी बधाई दूंगा और उनसे एक ही बात कहूंगा कि राजनीति में जब आदमी बढ़ता है, तो लोग दो चीज़ें देखते हैं कि राजनीतिक छवि कैसी है और प्रशासनिक छवि कैसी है। राजनीतिक छवि तो सबने देख ली है। अब उनसे उम्मीद है कि वे अपनी प्रशासनिक छवि दिखाएंगे। हम लोगों ने 6 महीने का समय दिया है। इसका यह मतलब नहीं है कि हमने उनको कोई ब्लैंक कागज दे दिया है।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: No, please. ...*(Interruptions)*... Please. Please. ...*(Interruptions)*... Nareshji, address the Chair and proceed. ...*(Interruptions)*... Address the Chair and proceed. बोलिए, बोलिए।

श्री नरेश अग्रवालः हमारी ये बहन यहां पहली बार आई हैं। अभी इनको भी कुछ सीखने को मिलेगा और शायद आज ही कुछ अनुभव मिल जाए। श्रीमन्, मैं कह रहा था कि दो अनुभव होते हैं। एक प्रशासनिक अनुभव होता है और एक राजनीतिक अनुभव होता है। राजनीतिक अनुभव भी देखने को मिलेगा। हमने 6 महीने का समय दिया है। मीडिया के लोग आज भी हमसे पूछ रहे थे कि उत्तर प्रदेश में कत्ल होने लगे हैं। मैंने कहा कि हमारी सरकार होती तो तब तो होता कि कानून-व्यवस्था नहीं है, लेकिन हम अभी कोई कमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि आपने बहुत फायदे किए हैं। आपने चुनाव के समय कहा था कि कैबिनेट पहली बैठक में किसान का कर्ज़ा माफ होगा और बूचड़खाने बंद हो जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश की सरकार नहीं कर पा रही है, तो कम से कम आप दिल्ली की सरकार से करा दीजिए। कांग्रेस के लोग तो कर्ज़ा माफी के लिए PM से मिलने गए थे। हम सब लोगों ने कहा था कि अगर इस देश के किसान का कर्ज़ा माफ नहीं हुआ, इस देश के किसान ने अगर तरक्की नहीं की, तो उचित नहीं होगा। मैं इसको दुर्भाग्य मानता हूं कि बजट तैयार करते समय वित्त मंत्री देश के पूंजीपतियों को, देश के उद्योगपतियों को बुलाते हैं, लेकिन किसानों से कभी सलाह नहीं लेते हैं कि बजट किस प्रकार बनाना चाहिए। इसीलिए GDP में एग्रीकल्चर का प्रतिशत निरंतर गिरता चला गया। यह प्रतिशत किसी जमाने में 42 प्रतिशत था। आज हम 19 per cent पर आ गए हैं। हमें यह सोचना चाहिए, हमें इस पर विचार करना चाहिए। अगर हम नहीं सोचेंगे और विचार नहीं करेंगे, तो हमारे सामने एक विशेष परिस्थिति खड़ी हो जाएगी। इन्होंने बहुत वायदे किए हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि वे अपने वायदों को पूरा करें। मैं मानता हूं कि जब संसाधन कम होते हैं, तो बजट बनाकर सबको लाभान्वित करना बड़ा मुश्किल काम होता है। जब मैं मंत्री था, तो मैं भी देखता था कि हमारी GDP घट रही है। हमें यह भी देखना है कि हमने क्या वायदा किया और कहां पर हम पहुंच गए हैं। हालत यह है कि चीन ने हमारी पूरी मार्केट पर कब्जा कर लिया है। किसान को MSP नहीं मिल रही है। आज हमार सामने, विश्व में एक अजीब स्थिति खड़ी हो गई है। आज ऐसा लगता है कि विश्व का कोई देश हमारे साथ नहीं है। कश्मीर अपने आप में जल रहा है। हम यहाँ सिर्फ वायदा करते हैं कि जब देश का प्रश्न आएगा, तो हम सब देश के साथ खड़े होंगे, लेकिन जहाँ राजनीति की बात आएगी, हम राजनीति करने में कहीं दूर खड़े नहीं होंगे। हम साधु नहीं हैं, हम राजनीतिक व्यक्ति हैं। मैं इन चार लाइनों के साथ बजट भाषण शुरू करूंगाः-

"हवा का जोर सदा एक सा नहीं रहता,
कहाँ तलक ये चिराग़ों को आजमाएगी।
कभी तो होगा उजालों का राज यहाँ,
कभी तो रात चिरागों से हार जाएगी।"

हम राजनीतिक व्यक्ति हैं, कभी हार परमानेंट नहीं मानते, कभी जीत परमानेंट नहीं मानते। हमने बहुत लहरें देखी हैं। हमने 1971 की लहर देखी, 1977 की देखी, 1980 की देखी, 1984 की देखी, 1989 की लहर भी देखी। देश में बहुत लहरें आईं। यही बीजेपी, किसी एक लहर में पार्लियामेंट में, लोक सभा में केवल दो पर रह गई थी। ...(**व्यवधान**)... मेरे ख्याल से गिरिराज सिंह जी को याद होगा एक

[श्री नरेश अग्रवाल]

ज़माने में यही बीजेपी दो की संख्या पर रह गई थी। उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ती चली गई। राजनीति को कभी भी परमानेंसी में नहीं लेना चाहिए, राजनीति temporary है। मैं तो कहूंगा कि राजनीति में "भूतपूर्व" शब्द ऐसा है, जो परमानेंट है, बाकी पद परमानेंट नहीं है। यदि हम यही सोचकर चलेंगे ...(**व्यवधान**)...

श्री आनन्द शर्मा (हिमाचल प्रदेश): यह एक ऐसा भूत है, जिसका कोई इलाज नहीं है।

श्री नरेश अग्रवाल: हाँ, इसका कोई इलाज नहीं। ...(**व्यवधान**)... उपसभापति जी, तीन साल पहले, जब इनकी सरकार आई थी, इन्होंने promise किया था कि हम जीडीपी आठ परसेंट से ऊपर ले जाएंगे। यह घटती चली गई और आज सात परसेंट पर है। इनके आंकड़े खुद बताते हैं। जब नोटबंदी हुई थी, तो पूर्व प्रधान मंत्री और देश के बहुत बड़े economist आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने इस बात को कहा था कि आप तैयार रहिए, हो सकता है कि दो परसेंट जीडीपी गिरे। जब उन्होंने यह बात कही थी, तब लोगों ने इसको हँसी में लिया था, लेकिन यह सत्यता कहीं न कहीं दिखाई दे रही है। अगर जीडीपी निरंतर गिरती चली गई, तो हमारे सामने एक बड़ी भारी चुनौती खड़ी होगी। आज हम अपनी जीडीपी का 19 प्रतिशत विश्व को सिर्फ ब्याज देने में अदा कर रहे हैं, क्योंकि हम विश्व से कर्ज़ ले रहे हैं। हम उनको जीडीपी का 19 प्रतिशत सिर्फ ब्याज के तौर पर दे रहे हैं, बाकी और प्रशासनिक खर्चे, तमाम योजनाएँ आदि, यदि जीडीपी बहुत ज्यादा गिरी तो देश में बेरोजगारी की क्या हालत होगी, क्या आपने कभी इस पर सोचा है? अगर जीडीपी कहीं छह परसेंट पर आ गई, तो हो सकता है कि हमारे नौजवान कहीं सड़कों पर न आ जाएँ। ...(**व्यवधान**)... चलिए, आनन्द शर्मा जी कह रहे हैं कि हमने तो बहुत बार उठाया कि सब पर पे कमीशन लागू हो रहा है, सिर्फ एम.पीज. को पे कमीशन नहीं दे रहे। सबका पे कमीशन लागू हो गया, अब तो चपरासी की तनख्वाह भी हम लोगों से ज्यादा हो गई। श्री मुख्तार अब्बास नक़वी साहब, आपका सौभाग्य है, आप तो नेता सदन हैं, हम आपको नेता सदन मान रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... हैं ही नहीं, नेता सदन, तो आप ही हैं नेता सदन।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You have promoted him!

SHRI NARESH AGRAWAL: Yes, Sir; I am promoting him.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Then, the Chair also has to agree! *...(Interruptions)...*

श्री नरेश अग्रेवाल: आप एग्री हैं, पूरा सदन एग्री कर रहा है।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN (Tamil Nadu): Sir, the entire House agrees.

श्री नरेश अग्रवाल: पूरा सदन एग्री कर रहा है। आज आप घोषणा कर दीजिए। ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: The Chair has not agreed! *...(Interruptions)...*

श्री नरेश अग्रवालः आज आप घोषणा कर दीजिए।

श्री राम विचार नेताम (छत्तीसगढ़)**:** माननीय सदस्य आपके नेतृत्व में आपका डेलिगेशन मिला था, उसके बारे में भी बता दीजिए कि वहाँ से क्या उत्तर मिला।

श्री नरेश अग्रवालः सुन लीजिए साहब।

श्री उपसभापतिः बोलिए, बोलिए।

श्री नरेश अग्रवालः मैं पी.एम. से मिलने गया था। मैंने पी.एम. से कहा, पी.एम. ने कहा कि हम विचार कर रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के 12-14 एम.पीज. मिलने गए। हमारे बाद उनका नंबर था। वे लौटकर आए, तो मुँह लटकाया हुआ था, मालूम हुआ कि इतना डाँटा बीजेपी वालों को। ...(**व्यवधान**)... 12-14 एम.पीज. गए थे, कहा कि साहब, एम.पीज़. की तनख्वाह बढ़ा दीजिए। मैं बैठा था, जब लौटकर आए, तो देखा, सब मुँह लटकाए हुए हैं। मैं नाम नहीं लूंगा कि मैंने कैसे किस से पूछा, पर वे कहने लगे कि आज हम लोगों को बहुत डाँट पड़ी है।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मुख्तार अब्बास नक़वी): नरेश जी, यह हुआ कि आपने प्रोत्साहित किया था, लगता था कि सब कुछ ठीक है, इसलिए उसमें यानी आपके प्रोत्साहन में लोग चले गए, लेकिन लौटकर आए तो उलटा हुआ।

श्री नरेश अग्रवालः तो ऐसा हुआ। चूंकि आप पूछ रहे थे कि एम.पीज़. मिलने गए, तो क्या हुआ, तो हमने बताया कि यह हुआ।

प्रो. राम गोपाल यादव (उत्तर प्रदेश)**:** अब तो उम्मीद इसलिए है कि जिन्होंने रिपोर्ट में रिंकमड किया था, वे उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हो गए। अब तो ध्यान रखना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए।

श्री नरेश अग्रवालः हां, यह भी बात ठीक है। योगी जी उस कमेटी के चेयरमैन थे, जिन्होंने रिकमंड किया था। वे उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री हो गए हैं तो इस सम्मान में ही घोषणा हो जानी चाहिए क्योंकि वे देश के सबसे बड़े राज्य के मुख्य मंत्री हो गए हैं। श्रीमन्, अभी झटका लगा है, इसलिए हम लोगों को फ्लो में आने में समय लगेगा।

श्रीमन्, मैं कह रहा हूँ कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ हमारी एक परसेंट रह गई है, जो नए आंकड़े आए हैं उसमें हम एक परसेंट से भी नीचे चले गए हैं। देश में केवल 4 परसेंट लोग इन्कम टैक्स दे रहे हैं, बैंक का एनपीए बढ़ रहा है और हर साल करीब 20 हजार करोड़ रुपए अपने बजट से हम बैंकों को दे रहे हैं। चिदम्बरम जी बैठे हुए हैं, मैंने इनसे भी कई बार कहा था कि हम अपना पैसा बैंकों को क्यों दें? आज बैंक के चेयरमैन की हालत यह है, आप एम.पी. की बात को छोड़ दीजिए, मंत्री जी अगर चेयरमैन को फोन कर दें तो चेयरमैन कहता है कि अच्छा, मंत्री से फोन कराया है और फिर काम उल्टा कर देता है। आप कहें, तो मैं मिसाल दे दूं। मैं कहना नहीं चाहता हूं, तीन दिन पहले का किस्सा है, मैंने किससे फोन कराया और उसका क्या रिजल्ट आया? बैंक के सीएमडी पर नकेल कसनी होगी। अभी 7000 करोड़

[श्री नरेश अग्रवाल]

रुपए माफ कर दिए, ऐशो-आराम पर वे कितना पैसा खर्च कर रहे हैं, इस बारे में कभी किसी ने सोचा है। सारा इंडस्ट्रियल सेक्टर बंद हो रहा है। आईएमएफ ने भी अपनी रिपोर्ट में दिया है कि जीडीपी और गिरेगी। मैं चाहूंगा कि जब वित्त मंत्री जी जवाब दें, तो सही आंकड़ों के तथ्य पर बता दें कि जीडीपी रियल कितना है? क्योंकि उनके आंकड़ों से तो न महंगाई है, न जीडीपी गिरा है, देश ठीक चल रहा है और हम विश्व में बहुत ऊपर चले गए हैं, लेकिन अगर सही आंकड़े बताए जाएं, तो मैं कहूंगा कि देश कम से कम इतना तो जान सकेगा कि देश के सामने क्या तकलीफ है?

श्रीमन्, हम सब लोगों ने नोटबंदी का विरोध किया, लेकिन हम चाहते थे कि काला धन वापस आए। मैं प्रधान मंत्री जी को बधाई दूंगा कि वे जनता को समझाने में सफल हो गए, क्योंकि राजनीति में वही आदमी बढ़िया होता है, जो जनता को समझाने में सफल हो जाए। वे गरीब को बताने में सफल हो गए कि हमने नोटबंदी में अमीर को गरीब बना दिया। इस देश में सरकारें नारा देती हैं कि हम गरीबी हटाएंगे, लेकिन इस सरकार ने नारा दिया कि हम अमीरी हटाएंगे। आप इसमें सफल हुए, अमीर-गरीब के बीच की खाई बढ़ी। हम उनसे कहते रहे कि कोई उद्योगपति लाइन में नहीं लगा, लेकिन उनको लगा कि जन धन खाते में रुपया आ जाएगा। हम भी उन्हें साल, दो साल का समय दे रहे हैं, पार्लियामेंट के चुनाव आ जाए, तो बहुत अच्छा है। हम सब यह जानना चाहते हैं कि नोटबंदी से पहले रिजर्व बैंक ने कितने हजार और पांच सौ के नोट जारी किए थे, क्योंकि आप कहते हैं कि 82 परसेंट, 88 परसेंट नोट आए, जो हजार और पांच सौ के नोट मार्केट में थे, उनकी फिगर 14 लाख 72 हजार करोड़ की आई थी। तो ये कितने जारी हुए थे और नोटबंदी के बाद कितने जमा हुए? मैं बिल्कुल साफ जानना चाहता हूँ कि कितने जारी हुए और कितने जमा हुए?

श्री आनन्द शर्माः अभी तक गिनती चल रही है।

श्री नरेश अग्रवालः क्या काले धन के रूप में कोई पैसा आया? हम लोगों ने विदेश से काला धन लाने की बात की थी, क्योंकि चुनाव में सवाल था कि विदेश से काला धन लाएंगे, मगर ये तो देश में काला धन खोजने लगे। पनामा से हजारों कंपनियों का आया कि पनामा में माध्यम से हजारों कंपनियां पनामा में बनीं और हिंदुस्तान का ब्लॅक मनी पनामा में व्हाइट हुआ। हिंदुस्तान में एफडीआई के माध्यम से वहां चला गया। सरकार को एक-एक नाम मालूम है। पेपर्स में तमाम नाम आए। स्विट्जरलैंड के बैंकों में किस-किस का पैसा जमा है, तमाम नाम आए, लेकिन क्या वह बताया गया? देश में आखिर काला धन कितना है, पता तो लगे! अब आपने नए नोट कितने जारी किए? आपने कह दिया कि नए नोट पर हमारी दो रुपए छपाई आई, तीन रुपए छपाई आई, लेकिन आप कागज का मूल्य तो बता नहीं कि नोट के कागज का मूल्य क्या है? खाली छपाई का नहीं, कागज का मूल्य भी आप बताइए। फिर यह दो हजार रुपए के नकली नोट अभी से बाजार में आ गए, तो आपने नए नोट छापने में कौन सी सेफ्टी रखी? आप कहते हैं कि हमने इसमें higher security रखी है, तो फिर कहाँ से नकली नोट आ रहे हैं! मैं रोज़ पढ़ लेता हूँ कि आज वहाँ दो हजार रुपए के नकली नोट ...(**व्यवधान**)...

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. संजीव कुमार बालियान): वे चूरन वाले नोट हैं।

श्री नरेश अग्रवाल: चलिए, चूरन वाले समझ कर मान लीजिए, लेकिन आप खुद ही कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं। यह आपका कहना है, यह मेरा कहना नहीं है। मैं यह बात पूछना चाहता हूँ कि हम जहाँ से नोट का कागज ले रहे हैं, अगर वहीं से पाकिस्तान और बांग्लादेश भी कागज ले रहे हैं और डाई भी वहीं से ले रहे हैं, तो यह क्यों है? यह हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश से नकली नोट हमारे पास आ रहा है। आप इस चीज पर कम से कम गौर तो करें। अगर आप यह भी बता दें कि अब तक कितना काला धन विदेश में है और वह कब तक वापस आएगा, तो शायद इस देश पर आपका बहुत बड़ा अहसान होगा।

हम सब किसान की बात करते हैं। अभी हमने कहा था कि किसान की कर्ज माफी की बड़ी इच्छा है। कांग्रेस ने एक बार उनका कर्ज माफ किया था। प्रधान मंत्री जी चुनाव में कहते रहे कि यूपी कैबिनेट की पहली बैठक में कर्म माफ हो जाएगा। हम वह mechanism नहीं समझ पाए। हमारे मित्र बैठे हैं, वे मुजफ्फरनगर से सांसद हैं और मंत्री भी हैं, ये शायद हमें ज्यादा अच्छा mechanism देंगे कि नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्ज राज्य सरकार कैसे माफ कर सकती हैं? यह कौन सा नया mechanism पैदा हो गया? अगर इसे एक राज्य सरकार माफ करेगी और उसका खर्च आप उठाएंगे, तो जो देश के अन्य राज्य हैं, वहाँ के किसानों का क्या होगा? उन राज्यों के सामने क्या समस्या पैदा होगी? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CMD, अरुंधती भट्टाचार्य ने खुल कर विरोध किया कि किसानों का कर्ज माफ नहीं होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... चलिए, आप घोषणा कर दीजिए। आप ही इसकी घोषणा कर दीजिए, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आपने तो कह दिया कि हम 14 दिन में गन्ना किसानों का पैसा भी दे देंगे। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की CMD ने खुल कर विरोध किया और उन्होंने कहा कि अगर हम ऐसे बैंकों का किसानों का कर्ज माफ करते रहे, तो भविष्य में किसान जो कर्ज लेंगे, वे कभी उसे अदा नहीं करेंगे और उससे बैंकों की स्थिति और खराब होगी। आज हम dilemma में हैं। किसी को पता ही नहीं है कि आप किसानों का कर्ज माफ करेंगे या नहीं। कल यूपी कैबिनेट की बैठक हुई। हम लोग बड़ा इंतजार कर रहे थे कि कम से कम एक राज्य में तो किसानों का कर्ज माफ होगा, क्योंकि जब 2012 में हमारी सरकार बनी थी, तो हमने भी किसानों का कर्ज माफ किया था। हमारा अधिकार था राज्य को-ऑपरेटिव बैंक का कर्ज माफ करने का, हमारा अधिकार था भूमि विकास बैंक का कर्ज माफ करने का, हमने अपने उस अधिकार का प्रयोग किया, लेकिन हम नेशनलाइज्ड बैंकों का कर्ज तो माफ ही नहीं कर सकते थे। मैं चाहूँगा कि कर्ज माफी पर यह सरकार स्पष्ट उत्तर दे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा।

आपने कहा था कि आप किसान को उपज का डेढ़ गुणा मूल्य देंगे। नोटबंदी में धान की जो कीमत हुई, सबको मालूम है। आप किसान की सब्सिडी और कम कर रहे हैं। ...(**व्यवधान**)... अगर आप हर चीज़ को वोट में लेंगी, तो बहुत मुश्किल सामने आ जाएगी। हमको चुनाव जीतते हुए 40 साल हो गए, आप पहली बार जीती हैं, अभी आपको राजनीति के बारे में ज्यादा पता नहीं है। हमको चुनाव जीतते हुए लगातार 40 साल हो गए। ...(**व्यवधान**)... अब भी जीती गए, इस लहर में भी जीते। जब

[श्री नरेश अग्रवाल]

आँधी थी, उस आँधी में भी जीते। ...(**व्यवधान**)... हम जानते हैं कि प्रैक्टिकल क्या चीज है? हमसे अच्छा कटाक्ष कोई नहीं करता है। आप महिला हैं, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। मैं थोड़ा सीमाओं के अन्दर हूँ। ...(**व्यवधान**)...

डा. संजीव कुमार बालियानः मैंने पहले ही समझा दिया है।

श्री नरेश अग्रवालः आपने अच्छा किया। गिरिराज भाई हमारे लिए ठीक हैं, क्योंकि ये भी free for all हैं और हम भी free for all हैं। हम और गिरिराज भाई, दोनों ठीक हैं। ...(**व्यवधान**)...

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (साध्वी निरंजन ज्योति): खून एक ही है।

श्री नरेश अग्रवालः हम दोनों भाई हैं, खून तो एक ही होगा। लाल इनका भी है और लाल हमारा भी है, किसी का खून सफेद नहीं है। महोदय, सब्सिडी निरंतर कम हो रही है। आप खाद पर सब्सिडी कम कर रहे हैं, बीज पर कम कर रहे हैं और पानी का दाम बढ़ रहा है। किसान के इस्तेमाल की हर चीज़ का दाम बढ़ रहा है, लेकिन किसान को उसकी उपज का दाम नहीं मिल रहा। किसान से खरीद का मार्केट में आपने कोई सिस्टम नहीं रखा है। एफसीआई की हालत यह है कि भ्रष्टाचार वहां चरम सीमा पर है। स्टोरेज आपके पास है नहीं, हर साल यह बात कही जाती है। हिन्दुस्तान में करीब 50,000 करोड़ रुपए का खाद्यान्न इसलिए सड़ता है कि हमारे पास उसको रखने की उचित व्यवस्था नहीं है, कोल्ड स्टोरेज नहीं है, जिसके कारण अनाज और खाने की दूसरी चीज़ें सड़ जाती हैं। आखिर इन परिस्थितियों में हम किसान को कैसे जिंदा रखेंगे?

किसान के सामने एक बहुत बड़ी समस्या यह भी है कि उसकी जोत छोटी होती चली जा रही है। आजादी के बाद चार-पांच पीढ़ियां खड़ी हो गईं, भूमि का बंटवारा होता चला गया और आज किसान दो एकड़, अढ़ाई एकड़ और तीन एकड़ का रह गया है। नौजवानों की रुचि खेती में कम हो गई है, वे नौकरियों की तरफ और व्यापार की तरफ भाग रहे हैं। ऐसे में आखिर किसान कैसे जिंदा रहेगा? उसकी भूमि उपजाऊ कैसे बनी रहेगी? देश के सामने यह एक बहुत बड़ी समस्या है। यह समस्या खाली यूपी के सामने नहीं है, यह समस्या पूरे देश के सामने है। भूमि का इतनी बार बंटवारा हो गया है और जोत इतनी छोटी हो गई है कि अगर हम एक ट्रेक्टर लें और उस ट्रेक्टर पर अगर सामान लोड करने का काम न करें, ढुलाई का काम न करें, तो हम ट्रेक्टर की किश्त बैंक को नहीं दे सकते। यह स्थिति पैदा हो गई है। इस तरह आखिर किसान का भला हम कैसे करेंगे? हम सब कहते हैं कि यह देश किसानों का है, हमारे देश की 70 प्रतिशत आबादी गांवों में रहती है, हम गांवों को बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन सच यह है कि गांवों की आबादी शहरों की तरफ भाग रही है। पूरे विश्व में शहर का रहने वाला आदमी गांव की तरफ जा रहा है। लंदन, अमरीका इत्यादि देशों में कोई आदमी शहर में रहना नहीं चाहती, इसलिए वह गांव की तरफ जा रहा है। इन देशों में गांवों में इन्फ्रास्ट्रक्चर उपलबध है, लेकिन भारत में शहरों की आबादी इतनी अधिक बढ़ती चली जा रही है कि आज कोई भी ऐसा शहर नहीं है, जो किलोमीटर्स में न बढ़ गया हो, चाहे वह छोटा शहर हो या बड़ा शहर हो। हर आदमी यह सोचता है

कि थोड़ा सा पैसा हो और हम शहर में रहने चलें, क्योंकि शहर में नौकरी के संसाधन भी उपलब्ध होंगे, हमारे बच्चों को शिक्षा भी मिलेगी और बिजली भी मिलेगी। यह जो उल्टा चलन है, इस चलन को हमें रोकना पड़ेगा। किसानों की आत्महत्याओं को भी हमें रोकना पड़ेगा। अगर हमने इस पर अभी भी रोक नहीं लगाई, तो हमारा दुर्भाग्य होगा।

हमारा एक कहना यह भी है कि किसान की उपज का मूल्य तय करने के लिए आईएएस लोगों की कमेटी बना दी जाती है। जब मूल्य तय होता है, तो वह कमेटी बड़ा अहसान करती है कि गेहूं का MSP 20 रुपए बढ़ा दिया गया, दाल का MSP 15 रुपए बढ़ा दिया गया।

श्रीमन्, अगर हम किसान को प्रोत्साहन नहीं देंगे, तो वह उचित नहीं होगा। आज हमारे यहां दाल का कितना इम्पोर्ट है? बालियान जी, आप स्वयं किसान हैं। मैं जिन बातों को उठा रहा हूं, उनमें किसानों की असलियत को उठा रहा हूं। गेहूं की लागत कीमत 1950 रुपए है और उसका MSP 1650 रुपए है। जो लोग धान और गेहूं की बाली में फर्क न पहचानते हों, उन आईएएस लोगों को इसके बारे में क्या मालूम? ऐसे लोगों से आप कहें कि आप किसान की उपज की कीमत तय कर दीजिए, तो किसान को कहां से न्याय मिलेगा? एक बार शरद जी जब मंत्री थे, तब हमने उनसे एक सवाल पूछा था, उसके जवाब में उन्होंने बताया था कि किसानों के लिए जो सलाहकार समिति बनी थी, उसमें टाटा और अम्बानी वगैरह सदस्य थे। प्रश्न के जवाब में यह लिखा था, वह जवाब मैं रिकॉर्ड से निकाल सकता हूं। अगर टाटा, अम्बानी और गोदरेज जैसे बड़े लोग किसान को एडवाइस देंगे, तो किसान का भविष्य क्या होगा?

महोदय, मेरा सरकार से एक अनुरोध है कि एमएसपी तय करने की कमेटी में कम से कम दो योग्य किसान, जिनको वे उचित समझें, जो सबसे प्रगतिशील किसान हों, उनको सदस्य बनाया जाए, जिससे वे किसानों का पक्ष भी रख सकें। उपसभापति महोदय, देश में import हो रहा है। आज सारी दालें म्यांमार, कनाडा और अन्य देशों से आयात की जा रही हैं। जब श्री आनन्द शर्मा जी, वाणिज्य मंत्री थे, तब से ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कितना ज्यादा बिजनेस कर रहा है, उसमें कितना बड़ा घालमेल है, यह सभी को पता है। एक दिन यह विषय श्री शरदा यादव जी ने उठाया था। आज हम गेहूं और शूगर का इम्पोर्ट कर रहे हैं। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा, तो किसानों को कहां से और कैसे उनकी उपज का मूल्य मिलेगा? अगर शूगर मिल और किसान, दोनों ही जिन्दा नहीं रहेंगे, तो भी ठीक नहीं होगा। हम दाल की MSP रु. 3,000/- रख रहे हैं और बाहर से दाल रु. 4,000/- प्रति क्विंटल आ रही है। ऐसा क्यों किया जा रहा है? हम किसान को क्यों नहीं प्रोत्साहित करते हैं? क्या हमारे देश का किसान कमजोर है या हमारे देश का किसान अनभिज्ञ है? वह खुद ही इतना अनाज पैदा कर देगा जिससे आयात करने की आवश्यकता ही नहीं रहेगी। आज वह जमाना गया जब अमेरिका से लाल गेहूं हिन्दुस्तान आता था।

श्री राजीव शुक्ल (महाराष्ट्र): माननीय उपसभापति जी, आज विदेशों से गेहूं आयात किया जा रहा है। आज zero per cent import duty कर दी गई है। हमें बताया गया है कि देश में गेहूं का उत्पादन लगभग नौ लाख टन होने की संभावना है। यदि ऐसा है और विदेश से गेहूं आयात किया जाएगा, तो देश के किसान तो मारे जाएंगे।

श्री आनन्द शर्माः ज़ीरो इम्पोर्ट ड्यूटी कर दी गई है।

श्री नरेश अग्रवालः उपसभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि इन्होंने खाद्य पदार्थ पर जो import duty खत्म की है या उसे ज़ीरो परसेंट कर दिया गया है, उसे इतना बढ़ा दिया जाए जिससे खाद्य पदार्थों का आयात रुक जाए। यदि ऐसा होगा, तो देश का किसान अपने देश में ही बहुत खाद्यान्न पैदा करेगा, जिससे देश की जरूरत पूरी हो जाएगी, लेकिन उसे उसकी उपज का डेढ़ गुना दाम मिलना चाहिए। यदि ऐसा होगा, तो मैं सबसे अच्छा समझूंगा।

महोदय, हम सब गरीबी मिटाने की बात करते हैं, लेकिन आज़ादी के इतने सालों के बाद हम अभी तक गरीबी की परिभाषा तय नहीं कर पाए हैं। प्लानिंग कमीशन, जो अब नीति आयोग बन गया है, उसने तय किया था कि गांव में रु. 18.00 प्रतिदिन कमाने वाला गरीब नहीं रहेगा और शहर में जो रु.23.00 कमाता है, वह गरीब नहीं रहेगा। हम सब ने इसे चैलेंज किया था। हम सब ने इसका विरोध किया था। हमारा कहना था कि 18 रुपए में तो चाय भी नहीं मिलती है। अब 10 रुपए प्रति कुल्हड़ के हिसाब से स्टेशन पर चाय मिलने लगी है। रु. 18.00 प्रति दिन में आप कैसे गुजारा करेंगे? अब तक गरीबी की परिभाषा तय करने के लिए चार कमीशन बैठ चुके हैं। एन.सी. सक्सेना कमीशन, अर्जुन सेनगुप्ता कमीशन, तेंदुलकर कमीशन और रंगराजन कमीशन। हर कमीशन ने अपनी रिपोर्ट दी है। अब शायद आपने कोई पांचवां कमीशन भी बैठा दिया है, लेकिन आप कब तक कमीशन बैठाएंगे? आखिर आप कब तक बीपीएल की परिभाषा करेंगे और देश में गरीबी रेखा आप कहां पर मानेंगे? मुझे तो लगता है कि आप सिर्फ आंकड़ों में गरीबी खत्म कर देंगे, तो हो सकता है किं आकड़ों में गरीबी खत्म हो जाए, लेकिन वस्तुतः तो गरीबी खत्म नहीं होगी। हमें यह देखना पड़ेगा कि जिस देश में 30 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीब हों, ...(**व्यवधान**)...

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Do you need a Commission to decide what poverty is?

श्री नरेश अग्रवालः उपसभापति जी, मैं कमीशन नहीं चाहता हूं। कमीशन बनाना, तो समस्या को टालने वाली बात है। मेरा कहना है कि सरकार अपनी विल पॉवर से घोषणा करे। देश में गरीबी कैसे खत्म होगी, आखिर गरीबी की कोई सीमा रेखा तो तय करे। हम टालते जाते हैं। जब हम विपक्ष में होते हैं, तो तमाम भाषण देते हैं।

महोदय, आज मैं व्हाट्सऐप पर एक मैसेज देख रहा था, जिसमें आसाराम बापू जी से सभी बड़े-बड़े नेता आशीर्वाद ले रहे थे। मैं नाम नहीं लूंगा कि उसमें कौन-कौन थे। आज ही मैं देख रहा था कि आसाराम बापू के सामने हमारे वे लोग, जिन्हें हम देश का कर्णधार मानते हैं और जिन्हें हम अपना आदर्श मानते हैं, वे सभी बापू जी के सामने झुके हुए थे और बापू जी उन्हें आशीर्वाद दे रहे थे और बापू जी अब जेल में हैं। किस इल्जाम में पड़े हैं, यह सब जानते हैं।

महोदय, हमें गरीबी की कहीं न कहीं एक सीमा तय करनी चाहिए और हमें गरीबी को समाप्त करना चाहिए। इसके लिए भले ही हमें बीपीएल की संख्या बढ़ानी पड़े, लेकिन एक संकल्प होना

चाहिए कि देश में कोई भूखा नहीं सोएगा, देश में कोई नंगा नहीं रहेगा, देश में कोई बिना मकान के नहीं रहेगा। और देश में एजुकेशन बढ़ेगी। अगर हम देश की इतने सालों की आजादी के बाद यह भी नहीं कर सके, तो आजादी का क्या फायदा? देश में इतना बजट खर्च हो रहा है, आखिर यह कहां जा रहा है? इन चीज़ों को देखिए। देश से भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए, इस बात के हम भी पक्ष में हैं। देश से भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा, उसकी कोई रूप-रेखा बनेगी, कोई मानक तय होंगे, तभी भ्रष्टाचार खत्म होगा।

महोदय, आज देश में बेरोजगारी की क्या हालत है, इसे सब जानते हैं। आज विश्व में हम सौभाग्यशाली हैं कि विश्व की टोटल आबादी के 60 प्रतिशत से ज्यादा हमारे देश में नौजवान हैं। चीन ने भी जब एक से ज्यादा बच्चे करने पर रोक लगाई, तो उसके सामने भी नौजवान आबादी का प्रश्न पैदा हो गया और उसने भी एक बच्चे की बजाय दो बच्चे पैदा करने का सिद्धान्त अपनाया। जापान में 80 प्रतिशत आबादी बुड्ढों की हो गई। जापान के पास सवाल है कि ओल्ड एज होम कहां बनें?

जापान को ऑस्ट्रेलिया में और न्यूजीलैंड में ओल्ड एज होम्स बनाने पड़े। हम सौभाग्यशाली हैं कि 60 परसेंट नौजवान हैं। तो आपने जो कहा था कि 2 करोड़ नौकरी प्रतिवर्ष देंगे, तब तो अब तक 6 करोड़ लोगों को नौकरी मिल गई होती। आपने पैरा मिलिट्री में नौकरी बंद कर दी, बैंकों में नौकरी बंद कर दी, सिविल एविएशन में सारी नौकरियाँ बंद कर दीं। तो आप अगर नौकरी बंद करते गए, तो कहीं ऐसा न हो कि देश के प्रतिभाशाली लोग, जो देश से पलायन कर रहे हैं, वह पलायन और न बढ़ जाए। यह हमारे देश के लिए दुर्भाग्य होगा। ...(**व्यवधान**)... इस सरकार ने यह अच्छा किया कि बुजुर्गों का एक मार्गदर्शक मंडल बना दिया, तय कर दिया कि इस उम्र वाले जितने बुजुर्ग होंगे, वे मार्गदर्शक मंडल में होंगे। यह एक नया रास्ता दे दिया। तो कम से कम हमारे देश में ओल्ड एज होम्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ...(**व्यवधान**)... अब आपसे शिक्षा ली, तो कहीं न कहीं हम भी उसको लागू करेंगे या नहीं लागू करेंगे? कहीं न कहीं कोई तो गाइडलाइन हमें माननी पड़ेगी या नहीं माननी पड़ेगी?

श्रीमन्, अभी तो मेरा बहुत समय बचा है। अभी तो आधा टाइम हुआ है। शिक्षा - हम सब मानते हैं कि एजुकेशन फॉर ऑल होनी चाहिए। मुझे याद है कि कांग्रेस एक बार सत्र में एक विधेयक लाई थी। डा. मनमोहन सिंह जी के जमाने में आया था - 'राइट टू एजुकेशन', 'एजुकेशन टू ऑल'। उसके लिए 'सर्व शिक्षा अभियान' चला, 'प्रौढ़ शिक्षा अभियान' चला, 'अनौपचारिक शिक्षा' चली। यह दुर्भाग्य है कि देश में इतने प्रकार की शिक्षा हो गई कि समझ ही नहीं पा रहे हैं कि कौन सी शिक्षा कहाँ होगी। कहीं उर्दू शिक्षा, कहीं संस्कृत शिक्षा तो कहीं कॉन्वेंट शिक्षा, देश में इतने प्रकार की शिक्षा हो गई कि कौन सी शिक्षा का आदमी शिक्षित माना जाए, यह बात हम समझ नहीं पाए। राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजा गया। केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को प्रस्ताव भेजा कि 65 परसेंट आप खर्च कीजिए, 35 परसेंट केन्द्र सरकार उस पर खर्च करेगी। राज्य सरकारों ने उस पर आपत्ति की और राज्य सरकारों ने कहा कि 65 परसेंट आप खर्च कीजिए और 35 परसेंट हम करेंगे और 'एजुकेशन टू ऑल' हम करेंगे। वह प्रस्ताव रुक गया। वह आज पेंडिंग पड़ा हुआ है। आप उस पर कोई निर्णय लीजिए। आज केरल में 100 परसेंट एजुकेशन है, तो देश का सबसे विकसित प्रांत अगर कोई है, तो केरल है। आज साउथ में एजुकेशन का प्रतिशत ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा डेवलपमेंट साउथ में है। सबसे ज्यादा पॉवर्टी अगर

[श्री नरेश अग्रवाल]

3.00 P.M .

कहीं है, तो नॉर्थ इंडिया में है, यूपी, बिहार, बंगाल, राजस्थान आदि में। पॉपुलेशन की ग्रोथ भी उन्हीं राज्यों में ज्यादा है, जिन राज्यों में एजुकेशन कम है। हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। हमारी आबादी जिस तेज़ी से बढ़ रही है, 2050 में आबादी के मामले में विश्व का सबसे बड़ा देश हम बन जाएँगे। कहाँ से इन्फ्रास्ट्रक्चर लाएँगे? आज वैसे भी हालत यह है कि ट्रेनों में जगह नहीं, बसों में जगह नहीं, प्लेन्स में जगह नहीं, सड़कों पर रोज जाम लग रहे हैं। आज चलना मुश्किल हो गया है। कहाँ कौन जाम में पड़ जाए, कहना मुश्किल है। एक दिन तो गडकरी जी डेढ़ घंटे जाम में फंस गए। वे एक शादी अटेंड करके गुरुग्राम से लौट रहे थे। तो अगर हमने एजुकेशन का सिस्टम ठीक नहीं किया -- मैं तो प्राइवेट सेक्टर को बधाई दूंगा कि कम से कम प्राइवेट सेक्टर ने एजुकेशन सिस्टम को -- यह ठीक है कि उन्होंने उसको कमाई का धंधा भी बनाया, लेकिन प्राइवेट सेक्टर ने कम से कम देश में एजुकेशन तो दी। आज हमारे देश की कोई भी यूनिवर्सिटी विश्व के मानकों पर खरी नहीं उतर रही है। आज जब विश्व के 100 यूनिवर्सिटीज के नाम आते हैं, तो हिन्दुस्तान की कोई युनिवर्सिटी उसमें नहीं आती है। आखिर इसका क्या कारण है? हमने यूजीसी पर कभी कमांड की? क्यों हम यूजीसी पर कमांड नहीं करते हैं, जबकि युनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन का यह काम है कि वह युनिवर्सिटीज़ का स्टैंडर्ड मेनटेन करे? 60 परसेंट युनिवर्सिटीज़ में टीचर्स नहीं हैं, इंटर कॉलेज में टीचर्स नहीं हैं, डिग्री कॉलेज में टीचर्स नहीं हैं। केन्द्रीय विद्यालयों की हालत बहुत खस्ता है। वहाँ टीचर्स नहीं हैं। हम जब टीचर्स नहीं रखेंगे, एजुकेशन की बात क्या करेंगे? आज एजुकेशन का स्तर गिरता जा रहा है। प्राइमरी स्कूल में भी यही हालत है। हमारे यहाँ एक आठवीं पास लड़का आया। उसने बोर्ड से फर्स्ट क्लास पास किया था, 90 परसेंट नम्बर थे। उसने बोला कि नौंवी में मेरा एडमिशन नहीं हो रहा है। मैंने प्रिंसिपल को बुलाया और कहा कियह फर्स्ट क्लास पास लड़का है, आप नौंवी में इसका एडमिशन क्यों नहीं ले रहे हैं? तब उसने मुझे उसके टेस्ट की जब कॉपी दिखाई, तो चारों सब्जेक्ट्स में ज़ीरो नम्बर पाया। तो अगर नकल से हमें कोई डिग्री मिलेगी, अगर नकल ही एजुकेशन का माध्यम होगा -- सिर्फ डिग्री?

कभी-कभी यह होता है, चुनाव में यह हो रहा था कि हम सिर्फ मार्कशीट के आधार पर नौकरी दे देंगे। ऐसा न हो कि मार्कशीट के आधार पर योग्य लोगों को नौकरी न मिले। जो पढ़ कर पास कर रहा है, उसके लिए 70 परसेंट..... हम लोग जब पढ़ते थे, तब अगर फर्स्ट डिवीज़न आ जाती थी, तो ऐसा समझते थे कि आकाश से तारे तोड़ लाए हैं। उस समय 4 या 5 बच्चे ही फर्स्ट डिवीजन में पास होते थे। जो लड़का फर्स्ट डिवीजन पास होता था, उसके बारे में ऐसा समझा जाता था कि वह बहुत brilliant लड़का है। अब तो 80 परसेंट बच्चे फर्स्ट डिवीजन पास होते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? हम AICTE पर नकेल क्यों कर रहे हैं? AICTE ने एजुकेशन कमाई का जरिया क्यों बना रखा है? हमने कभी इस पर विचार किया, इस पर सोचा? क्या पार्लियामेंट सिर्फ इसलिए है कि हमने अपनी बात कह दी, आपने लिख लिया और औपचारिकता पूरी हो गई? अगर वास्तविक रूप में जमीन पर चीज़ें नहीं उतरीं, तो हम देश का भला नहीं कर रहे हैं, हम इसलिए यहां नहीं बैठे है। हम यहां पर निर्णय लेने के लिए बैठे

हुए हैं। जनता ने हमें इसलिए यहां बैठाया है, क्योंकि यह पॉपुलर गवर्नमेंट है और पॉपुलर गवर्नमेंट में हमारे हित में तमाम निर्णय होंगे, लेकिन निर्णय नहीं हो रहे हैं। अगर निर्णय होते, तो हमें यह कहने की क्या आवश्यकता पड़ती?

आज गर्ल्स एजुकेशन कितनी है? हमारे देश में आज एक वास्तविक रूप से 55 परसेंट भी गर्ल्स एजुकेशन नहीं है, लड़कों की जरूर 70-75 परसेंट तक पहुंच गई है। अगर ऐसा ही रहा और लड़कियों को एजुकेट नहीं किया गया, तो आप कन्या भ्रूण हत्या कैसे रोकेंगे? क्या आपने कभी इस पर विचार किया है? आप लड़कियों की एजुकेशन को compulsory क्यों नहीं कर देते हैं? अगर लड़कियों की एजुकेशन compulsory हो जाएगी, तो परिवार नियोजन आने आप लागू हो जाएगा, लेकिन हमने एजुकेशन नहीं दी। हम एजुकेशन की ओर कदम नहीं बढ़ा रहे हैं। हमको इस पर विचार करना चाहिए और इस पर कोई कठोर निर्णय लेना चाहिए। अगर आप भी कठोर निर्णय न ले सकें, तो फिर मिलीजुली सरकारों से आप कैसे कठोर निर्णय की आशा करेंगे? मैं चाहूंगा कि आप कोई कठोर निर्णय लें और विश्वविद्यालयों को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं। जेएनयू में सब कूद पड़े। अब तो हम रोज पढ़ते हैं कि जेएनयू में आज यह हो गया, कल यह हो गया, एबीवीपी ने यह किया, एनएसयूआई ने यह किया, कम्युनिस्ट की ऑर्गेनाइजेशन ने यह किया। छोड़िए, हम एजुकेशन के सेंटर्स को राजनीति का अखाड़ा न बनाएं, बल्कि एजुकेशन के सेंटर्स को एजुकेशन का अखाड़ा रहने दें। वहां पर शिक्षा पर चर्चा होनी चाहिए कि कैसे अच्छी शिक्षा हो। हम कैसे देश का भला करें, अगर इस पर चर्चा होगी, तो बहुत अच्छा होगा। राजनीति करने के लिए तो अभी हम, आप, बहुत लोग हैं। अब तो यह है कि सभी लोगों को राजनीति में इंटरेस्ट हो गया। अब तो जो आईएएस रिटायर होता है, जो अधिकारी रिटायर होता है, वह 60 साल फाइलों पर मास्टर होता है और रिटायर होते ही वह कोई दल ज्वॉइन कर लेता है और हम, आप इतनी जल्दी उसको टिकट देते हैं, जैसे उसने कितना बड़ा sacrifice किया है। देश के पूर्व गृह सचिव फौरन मेम्बर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। अब मैं बहुत चीज़ें नहीं कहूंगा, हमारे मित्र हैं, भाई हैं, लेकिन राजनीति का भी कोई न कोई एक विद्यालय बना देना चाहिए कि जब तक वहां की डिग्री नहीं लाओगे, तब तक राजनीति में नहीं आ सकते हो। यह राजनीति हर एक के लिए नहीं है। ...(**व्यवधान**)... आज जिसे देखो, खाली हुआ, उससे पूछो कि क्या कर रहे हो, पहले जैसे था कि हम लैण्ड का काम कर रहे हैं, लेकिन आज ऐसा हो गया है कि सब कहते हैं कि हम राजनीति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? यह राजनीति करते-करते, वह राजनीति कम कर रहा होता है, दलाली ज्यादा कर रहा होता है। अब तो कहीं-कहीं ऐसा हो गया कि हर दूसरे घर पर दो लड़के राजनीति में आ गए और राजनीति का मतलब ठेकेदारी, पट्टेदारी। यही तो है, 50 लोग चले गए और डीएम मुर्दाबाद के नारे लगा दिए, डीएम ने कहा... चूंकि डीएम खुद ही इतना कमजोर है, क्योंकि उसकी कलम से इतने गलत काम होते हैं। अगर राजनीति की परिभाषा यह बना दी गई है, तो हमको गाली लगती है, क्योंकि जब हम ट्रेनों में चलते हैं, तो कहा जाता है कि नेता जी जा रहे हैं। 'नेता' शब्द गाली हो गया। अगर हम यह नहीं बताएं कि हम एमपी हैं और सेकंड क्लास या थर्ड क्लास में बैठ जाएं.... मैं इसी से संबंधित एक किस्सा सुना देता हूं। जितेन्द्र प्रसाद, हम लोगों के बीच में नहीं रहे हैं, एक बार हम दोनों लखनऊ मेल से लखनऊ जा रहे थे और मुरादाबाद के पास ट्रेन डिरेल हो गई, तो हम लोगों को उतरना पड़ा। नई

[श्री नरेश अग्रवाल]

ट्रेन आई, उससे हम सब लोग ले जाए जाने लगे, तो हम लोगों को मुरादाबाद से गजरौला तक पहुंचने तक में कितनी गालियां सुननी पड़ीं। हमने उनसे कहा कि भाई साहब, आप यह न बता देना कि आप एमपी हो या हम एमएलए हैं, इसको चुपचाप सुन लो। एक जमाने में 'नेता' शब्द आदर का शब्द था कि नेता जी आ रहे हैं। आज अगर 'नेता' शब्द गाली का शब्द हो गया है, तो हमें इसकी परिभाषा बदलनी पड़ेगी, अपना आचरण बदलना पड़ेगा। यह नहीं होना चाहिए कि कल तक रिक्शे का किराया नहीं दे पाते थे, आज MLA बन गए तो गाड़ी भी आ गई, पक्का मकान भी बन गया और सारी सुविधाएं उपलब्ध हो गईं। अगर हमारा स्वरूप ऐसा रहेगा तो नेता के प्रति लोगों के मन में विचार दूसरा होगा। हमें खुद अपना आचरण ठीक करना पड़ेगा। मैं समझता हूं कि अगर हम सब लोगों ने ऐसा नहीं किया तो धीरे-धीरे हमारा स्तर गिरता चला जाएगा और गिरता स्तर इस देश के प्रजातंत्र के लिए अच्छा नहीं है। मैं चाहूंगा कि शिक्षा पर आप विचार कर लें। मेरा ख्याल है कि मेरा बोलना सबको ठीक लग रहा होगा।

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री गिरिराज सिंह): आज लग ही नहीं रहा कि कौन बोल रहा है।

श्री नरेश अग्रवाल: मैं हरदम ऐसे ही बोलता हूं। जब मैं आपका भी स्टेटमेंट सुनता हूं तो अच्छा लगता है कि कम से कम बिहार में अभी भी कोई जयप्रकाश नारायण बाकी है, जो सही चीज़ों को बोल तो रहा है। अन्यथा आज राजनैतिक दलों में स्तर इतना गिरा हुआ दिखाई देता है कि प्रवचन सुनने को मिलते ही नहीं। लोगों को प्रवचन बोलने मे दिक्कत आने लगी है।

अब मैं बैंकों पर आता हूं। इंदिरा जी ने 1971 में बैंकों का nationalization किया था। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: अभी 4 मिनट बाकी हैं।

श्री नरेश अग्रवाल: अगर House allow कर दे, तो मुझे थोड़ा-सा बोलने दीजिए।

श्री उपसभापति: बोलिए, बोलिए।

श्री नरेश अग्रवाल: बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया गया था, क्योंकि तब पूंजीपतियों के Banks थे और गरीबों को सुविधा नहीं थी। राष्ट्रीकरण इसलिए किया गया था कि गरीबी हटाएंगे, बैंक ऋण देंगे, सस्ते ब्याज पर लोगों को ऋण उपलब्ध होगा, उद्योग-धंधे बढ़ेंगे, कुटीर उद्योग बढ़ेगा, देश में बेरोजगारी दूर होगी लेकिन आज बैंकों का NPA 12 per cent हो गया है। विश्व के किसी भी देश में बैंकों का NPA 12 per cent नहीं होगा। हम 20,000 करोड़ रुपए अपने बजट से देते हैं। मैं उस दिन पढ़ रहा था कि शायद सरकार ने ऐसा निर्णय लिया है कि अब हम अपनी तरफ से बैंकों को कुछ नहीं देंगे। विश्व में ब्याज का LIBOR rate एक से दो per cent से कहीं ऊपर नहीं है लेकिन हमारा कोई बैंक 14 per cent से कम ब्याज पर लोन नहीं देता है। आप किसानों के लिए एक-दो per cent पर लाएं, उसे क्यों नहीं आप LIBOR rate पर देते हैं? आप जितना भी कर्ज विश्व बैंक से ले रहे हैं, यूरोपियन बैंक से

ले रहे हैं, जापानी बैंक से ले रहे हैं, सारे बैंकों से आपको लोन एक या दो per cent ब्याज दर पर मिल रहा है, बल्कि एक per cent के आस-पास है, शायद 1.5 per cent है, लेकिन हम ले क्या रहे हैं? धीरे-धीरे जो Savings Bank खाते हैं, उनमें भी हम ब्याज दर कम करते जा रहे हैं। Old age लोगों का क्या हुआ, जो FD कराते थे और सोचते थे कि हमें 8-9 per cent ब्याज मिलेगा। उनकी ब्याज दर आज घटते-घटते 7 per cent तक आ गई। Savings Bank खातों में बैंक कहता है कि अब 3 निकासी से अधिक पर पैसे काटेंगे। उस दिन हमारे मित्र, सीताराम येचुरी जी कह रहे थे कि उन्होंने कोई निकासी भी नहीं की, फिर भी उनके 144 रुपए कट गए। एक नया ATM आ गया, अब तो App भी आ गया। क्या इस देश में ऐसी व्यवस्था लागू होगी कि हमें पैसा जमा करने पर भी ब्याज देना पड़ेगा? यदि ऐसा हुआ तो यह गरीब देश कैसे चलेगा? ठीक है कि आप Current Account वालों से लीजिए, उनसे कटौती कीजिए, Current Account से हम मना नहीं करते हैं, लेकिन Savings Bank and Fixed Deposits को तो इससे बचाइए। हर बैंक ने अपना Secret Act बना रखा है। Bank Secrecy Act कहता है कि बैंक के कौन बकायेदार हैं, इसे हम open नहीं करेंगे। Finance Committee में मैंने बहुत बार इसका विरोध किया कि गांव के एक गरीब पर अगर 10,000 रुपए भी कर्ज है तो आप तहीसल के gate पर लाल अक्षरों से लिख देंगे, लेकिन अगर पूंजीपतियों पर लाखों करोड़ रुपए बकाया है तो आप क्यों उनकी list प्रकाशित नहीं करना चाहते? आज आप declare कर दीजिए कि इस एक्ट को हम समाप्त करते हैं, कल देश के सारे अखबारों में अगर 100 बड़े बकायादारों के नाम आ जाएं तो देश के सामने एक नई क्रांति पैदा हो जाएगी, देश जान जाएगा कि किसके पास देश का कितना रुपया बकाया है और बैंकों में किसने कितना रुपया दिया। नोटबंदी में कितने बड़े लोगों का रुपया बदला गया, किन-किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की गई, आखिर कुछ तो पता लगे, कहीं तो जानकारी मिले। आप Students और किसानों के लिए 2 per cent या 3 per cent ब्याज पर ऋण देने की घोषणा कर दीजिए, क्योंकि बेरोजगारी है, लड़का पढ़कर निकलता है, मां-बाप अपनी पूरी जिंदगी लगा देते हैं लेकिन ब्याज नहीं दे पा रहे हैं। क्या हालत देश के सामने है? वे ब्याज नहीं दे पा रहे हैं, देश के सामने यह कैसी हालत है? अगर ऐसा किया जाए, तो मैं समझूंगा कि यह देश के साथ बहुत बड़ा न्याय होगा। आप कुछ स्टेप्स लीजिए। वित्त मंत्री जी यहाँ होते, तो मैं उनसे बहुत-सी चीज़ें कहता। मैं उनसे कहता कि वित्त मंत्री जी, ये-ये सुधार कीजिए। बैंकों के सीएमडीज़ को यह इंस्ट्रक्शन जानी चाहिए कि अगर कोई एमपी फोन करेगा, तो उसकी यह जिम्मेदारी होगी कि वह उस एमपी को रिप्लाई दे। मुझे इतने साल यहाँ हो गए, यहाँ मेम्बर्स ऑफ पार्लियामेंट बैठे हैं और उधर दूसरे साथी भी बैठे हैं। आप किसी भी बैंक के सीएमडी को फोन कर लीजिए, वह कभी लाइन पर नहीं आएगा और वह कभी लौटकर आपसे बात भी नहीं करेगा। आखिर ऐसा क्यों है? हमारा प्रोटोकॉल है और अगर हम बैंक से कुछ पूछना चाहते हैं, कोई बात करना चाहते हैं, हमारे यहाँ कोई बेरोजगार आया और हम उस बेरोजगार के संबंध में बात करना चाहते हैं, तो बैंक का सीएमडी हमसे बात नहीं करेगा! यह कौन-सी बात हुई? संतोष गंगवार जी, आप उनको इंस्ट्रक्शन्स दे दीजिए। आप ज्यादा मृदुभाषी हैं, ज्यादा सीधे हैं। राजनीति में सीधा होना बहुत अच्छा नहीं होता है, राजनीति में थोड़ा-सा टेढ़ा भी होना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... मैं इसी मारे कह रहा हूँ, शरीफ तो हम भी बहुत हैं, लेकिन हमारा सर्टिफिकेट दूसरी यूनिवर्सिटी से है, इनका

[श्री नरेश अग्रवाल]

सर्टिफिकेट -- हर साल बैंक से करीब 6-7 हजार करोड़ रुपए माफ होते हैं, यह माफी क्यों हो रही है? माल्या भाग गए, ललित मोदी भी भाग गए, तमाम और लोग जिन्होंने कर्जे लिए, उनके मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री संतोष कुमार गंगवार): उनको हमारी सरकार ने नहीं भगाया है। हम उन सबसे वसूली की कार्रवाई कर रहे हैं और बहुत मजबूत कार्रवाई कर रहे हैं। अभी कल या परसों भी एक सवाल पूछा गया था, तो उसके उत्तर में बताया गया है कि ऐसा किया जा रहा है। इसके तथ्य हम आपको बाद में बता देंगे।

श्री गिरिराज सिंह: इसलिए आप इन पर आरोप मत लगाइए, दुख होता है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल: हम आप पर आरोप नहीं लगा रहे हैं, लेकिन हम भी मंत्री थे, तब कह देते थे कि आवश्यक कार्रवाई की जा रही है, जल्द ही कार्रवाई की जाएगी। यह आश्वासन भी नहीं बनता है और कार्रवाई का अंग भी नहीं बनता है। इन शब्दों को राजनीति की डिक्शनरी से निकाल दीजिए। आज आप यह घोषणा कर दीजिए कि जितने बड़े बकायेदार हैं, वे तीन महीने के अंदर या तो ओटीएस कराएँ या बैंकों का रुपया जमा करें। वह रुपया बैंक में जमा होना चाहिए। ...(**समय की घंटी**)...

श्री उपसभापति: ठीक है, नरेश जी।

श्री नरेश अग्रवाल: सर, अभी तो बहुत समय है। हमने सोचा था कि मुझे एक घंटे तक बोलने का मौका मिलेगा।

श्री उपसभापति: आपको बोलते हुए 45 मिनट्स से ज्यादा हो गए हैं। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल: श्रीमन्, अब हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पर आते हैं।

श्री उपसभापति: ठीक है, आप पाँच मिनट और ले लीजिए।

श्री गिरिराज सिंह: अभी तो बजट पर बोलना है। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवाल: मैं तो बजट पर ही बोल रहा हूं। आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आपके जमाने में क्रूड ऑयल का रेट नहीं बढ़ा। कितनी सेविंग हुई। ...(**व्यवधान**)... मैंने वही कहा कि एक जमाने में 120 रुपए तक पहुँच गया था, आज 50-51 रुपए में ...(**व्यवधान**)...

श्री राजीव शुक्ल: 120 डॉलर।

श्री नरेश अग्रवाल: वह 120 डॉलर प्रति बैरल था, लेकिन आज वह बहुत गिर गया और बहुत सेविंग हुई। आपकी उत्पादन लागत पेट्रोल की 23 रुपए है और डीज़ल की 19 रुपए है। आप लोगों ने खुद ही इस सदन में यह जानकारी दी है। फिर आज क्यों 70 रुपये में पेट्रोल बिक रहा है, क्यों 60 रुपये में डीज़ल बिक रहा है? आप नेपाल और बंगलादेश जैसे पड़ोसी देशों को देख लीजिए कि वहाँ यह

किस रेट पर मिल रहा है। हम क्यों इतना टैक्स लगा रहे हैं? राज्य सरकारें इतना टैक्स क्यों लगा रही हैं? हम कहते हैं कि आप बता दीजिए। आप यह नोट कर लीजिए कि आप बताएँगे कि क्रूड ऑयल से कितने रुपये में हमारा पेट्रोल और डीज़ल बन रहा है। आप कैरोसीन ऑयल की सब्सिडी घटा रहे हैं, कैरोसीन ऑयल का राज्यों का कोटा घटा रहे हैं। आप कहते हैं कि हम धीरे-धीरे कैरोसीन-फ्री कंट्री कर देंगे, लेकिन अभी गाँवों में सबको बिजली उपलब्ध नहीं है। हमारी यह बहन ज्यादा जानती होंगी कि जब यह सरकार बनी थी, तब गैस सिलेंडर लगभग 500 रुपये का था, जो आज 800 रुपये का हो गया है, लेकिन उसकी कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है! "उज्जवला योजना" के नाम पर लोग यह भूल गए कि आज सिलेंडर की कॉस्ट कितनी हो गई है। आपने 500 रुपए के सिलेंडर को 800 रुपए का कर दिया।

श्री गिरिराज सिंहः देखिए, अभी आप ऋषि-वाणी बोल रहे थे, फिर आप गड़बड़ा रहे हैं। आप ऋणि-वाणी बोलिए। ...(**व्यवधान**)...

श्री नरेश अग्रवालः हम कतई नहीं गड़बड़ा रहे हैं। हम सत्य बोल रहे हैं, हम असत्य से दूर हैं। आज सिलेंडर की कीमत इतनी बढ़ गई, लेकिन कोई नहीं बोल रहा है। आखिर सरकार क्यों नहीं बताती कि हमने सिलेंडर की कीमत को इतना क्यों बढ़ा दिया? पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के दाम इतने हाई क्यों हैं? अगर आप इस देश में पेट्रोलियम पदार्थ सस्ते कर दें तो महँगाई अपने आप रुक जाएगी। आपको लगता है कि हमारा थोक सूचकांक गिरा, फुटकर सूचकांक गिरा, सरकार घोषणा कर देती है कि महँगाई घटी। महँगाई कहाँ पर घटी? आज 100 रुपये का नोट तो कोई जेब में रखना नहीं चाहता और अगर कहीं किसी भिखारी को एक रुपया या दो रुपये दिया जाए, तो शायद वह गाली देगा। दस रुपये से नीचे तो भिखारी भी नहीं ले रहा है आज इस देश में। तो हम आज कहां खड़े हैं, इस पर विचार करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? अगर क्रूड ऑयल की कीमत गिरती है, तो पेट्रोल की कीमत के बारे में आपने कहा कि हमने मार्केट पर छोड़ दिया है। पेट्रोलियम कम्पनियां मज़े करने लगीं और कहते हैं कि हम सरकार के अधीन नहीं हैं, हम फ्री हो गए। ऐसा पेट्रोलियम कम्पनियां कह रही हैं।

हमने एक दिन दवा का मामला उठाया था कि जेनेरिक ऑर नॉन-जेनेरिक दो दवाइयां जो आपने बनानी शुरू कीं, बस, मैं खत्म कर रहा हूं, क्योंकि और लोग भी बोलेंगे। स्वास्थ्य मंत्री जी ने अभी स्वास्थ्य नीति की घोषणा की है। स्वास्थ्य मंत्री जी पिछले दिनों सदन में स्वास्थ्य नीति की घोषणा कर रहे थे। अखबारों में बड़ा मोटा-मोटा विज्ञापन छपा कि यह सरकार जिम्मेदारी लेती है कि हरेक के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी सरकार लेगी कि कोई गरीब दवाई से वंचित नहीं होगा, कोई गरीब इलाज से वंचित नहीं होगा। आपने कैसे ले ली जिम्मेदारी? अस्पतालों में डॉक्टर्स नहीं हैं, सी.एच.सीज., पी.एच.सीज. खाली हैं। प्राइवेट डॉक्टर के पास चले जाओ तो वह इतनी जांचें लिख देगा, जिसमें उसका इतना कमीशन हो जाएगा। ब्रांडेड कम्पी की दवा और जेनेरिक दवा के नाम में सौ गुना अंतर है। आप जेनेरिक खरीदेंगे तो 10 पैसे की मिलेगी। आज विश्व में कहीं भी डॉक्टर एंटीबॉयटिक दवा लिखते नहीं हैं। यहां खांसी आ जाए, जुकाम आ जाए, छींक आ जाए, आप डॉक्टर के पास चले जाओ तो वह पहले 7 दिन के लिए एंटीबॉयटिक लिख देगा। कोई एंटीबॉयटिक की गोली 70 रुपए से कम नहीं है।

[श्री नरेश अग्रवाल]

कैसे आप दवा मुफ्त दे देंगे? आप हैल्थ पॉलिसी को डिक्लेयर करेंगे, जैसे पूरे वर्ल्ड में इंश्योरेंस पॉलिसी है, जो गरीब जिस अस्पताल में इलाज कराएगा बीमा कम्पनी उसकी जिम्मेदार होंगी पैसे के लेन-देन के लिए। तब तो हम समझें कि पॉलिसी बहुत अच्छी है। ...(**समय की घंटी**)... आपका डॉक्टर्स पर कोई कंट्रोल नहीं है, अस्पतालों पर कोई कंट्रोल नहीं है। एम्स में तीन-तीन साल के लिए मरीजों को तारीखें मिल रही हैं। एम्स में आप किडनी बदलवाने चले जाइए, हार्ट की दवा कराने चले जाइए तो छः महीने या एक सल से पहले आपको तारीख नहीं मिलेगी। सफदरजंग अस्पताल चले जाइए, जहां भीड़ लगी हुई है। ऐसे ही मैक्स वगैरह चले जाइए, प्राइवेट हॉस्पिटल तो बड़े-बड़े लोग जा सकते हैं, गरीब तो उसके अंदर घुस ही नहीं सकता। वहां दरबान नहीं घुसने देगा। कहां लाठी लेकर गरीब घुसेगा? तो आप कैसे स्वास्थ्य देंगे, आप यह तो बता दीजिए।

श्री उपसभापतिः नरेश जी, अब कंक्लूड कीजिए।

श्री नरेश अग्रवालः अब मैं खत्म किए देता हूं, डिप्टी चेयरमैन साहब का आदेश है। आप जो करिए सही करिए। जैसे पिछली बार उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया था कि किसी भी किडनी या किसी के हार्ट का इलाज होगा तो उसका बिल राज्य सरकार बियर करेगी। अब केन्द्र सरकार से घोषणा करा दीजिए, यदि कोई भी गरीब इलाज कराएगा तो उसका रिएम्बर्समेंट केन्द्र सरकार देगी। हम समझेंगे कि गरीबों का इलाज हो रहा है।

आप चुनाव-सुधार की बात कर रहे हैं। अभी परसों डिस्कशन के लिए यह आएगा। उत्तर प्रदेश में कितना पैसा खर्च हुआ? सर्वे में आया है कि 5,500 करोड़ रुपया पूरे देश में इस बार चुनाव में खर्च हुआ। आपने कह दिया कि अब कोई नकद दो हजार से ऊपर नहीं लेगा। तो यह रुपया कहां से आया? उत्तर प्रदेश में बी.जे.पी. के प्रत्याशी को एक-एक करोड़ रुपया दिया गया। इतना रुपया कहां से आया? कहां हुई चुनाव-सुधार की बात, कौन सा चुनाव-सुधार, वह एक-एक करोड़ रुपया कहां से आया? आखिर चुनाव-सुधार पर तो हम सब राजी हैं। इस पर परसों हम लोग डिस्कशन कर लेंगे।

महोदय, मैं इतना ही कहूंगा कि कम से कम विदेश नीति भी ठीक कर लीजिए। विश्व में हमारे देश के जो नागरिक मर रहे हैं, मारे जा रहे हैं, अमेरिका ने H1B वीज़ा खत्म कर दिया। तमाम हिन्दुस्तानी अमेरिका से वापस आ रहे हैं। कम से कम इन चीजों को फिर से रिव्यू कर लीजिए। जहां देश का प्रश्न आएगा, हम सब आपके साथ खड़े होंगे। हम राजनीति छोड़ने के लिए तैयार हैं, जब देश का प्रश्न आएगा, लेकिन जहां राजनीति का प्रश्न आएगा, हम जरूर अपने विचार देंगे, अपनी बातों को कहेंगे, हम सुधार भी करेंगे, आलोचना भी करेंगे। हमारी आलोचना को व्यक्तिगत मत लीजिएगा, हमारी आलोचना को यह समझ लीजिएगा कि विपक्ष ने हमको आईना दिखाया है, हम किस आईने को देखना चाहते हैं, यह हमारे ऊपर है। मैं समझता हूं कि अगर इन विचारों को लेकर हम सब राजनीति करेंगे, इस सोच के साथ हम आगे बढ़ेंगे तो इस राष्ट्र के निर्माण में कहीं न कहीं हमारा योगदान होगा। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बजट स्पीच समाप्त करता हूँ।

SHRI R. VAITHILINGAM (Tamil Nadu): Hon. Deputy Chairman, Sir, with the grace and blessings of hon. Amma, the late Chief Minister of Tamil Nadu, I stand here in the Upper House of Parliament to make my maiden speech.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: You can take a maximum of 20 minutes.

SHRI R. VAITHILINGAM: Thank you, Sir.

Sir, I heartily thank hon. Amma for this great gesture in making me a Member of this august House in 2016 and making me stand here before all of you to make this first-ever speech in this House. On this occasion, I would like to pay my rich tribute to hon. Amma.

[THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA) *in the Chair.]*

Even though she is not in our midst today, she lives on in everybody's hearts. Moreover, she had been a Member of this House. The able leadership of Amma is seen as an appreciation of the many welfare measures that hon. Amma has unleashed for the people of Tamil Nadu and her success is being lauded not only by the people of this country but also the entire Tamil population all over the world. They also recognize that hon. Amma has scored a hatrick having won the 2011 Assembly Elections, the 2014 General Elections and the 2016 Assembly Elections. As far as I am concerned, before making me an MP in this august House, she had made me an MLA three times, from 2001 to 2016. In those 15 years, she had made me a Minister in the Tamil Nadu Cabinet twice. I pay my respects to her for this.

Sir, coming to the Budget, to begin with, I once again pay my obeisance to hon. Amma for having given me this opportunity to stand here and participate in the discussion on the Budget presented by the hon. Finance Minister.

There are many pending issues with the Centre pertaining to Tamil Nadu, especially those regarding funds. They have been presented in the form of a memorandum to the hon. Prime Minister by the Chief Minister of Tamil Nadu on 27th February 2017.

Following the failure of the monsoon, Tamil Nadu is presently reeling under severe drought. A Central Team also visited Tamil Nadu to make an on-the-spot assessment of the drought situation from 21st to 24th January 2017. In this connection, I request the hon. Finance Minister to kindly accord sanction for the immediate release of ₹ 2,500 crores from the National Response Fund to the Government of Tamil Nadu for mitigating the drought situation.

[Shri R. Vaithilingam]

The House may also recall that Tamil Nadu experienced heavy floods in 2015, and also a severe cyclone, 'Vardah', in December 2016. This also has caused tremendous damage of life and property in Tamil Nadu. The State Government had assessed the requirement of funds with regard to cyclone 'Vardah' alone as ₹ 22,573 crores. I request the hon. Finance Minister to kindly allocate sufficient funds immediately.

Coming to GST, as a manufacturing State, Tamil Nadu is going to incur a huge financial loss. As a part of the road-map for implementation of GST, the Central Sales Tax rate was reduced from 4 percent to 3 per cent from 1.4.2007, and further brought down to 2 percent from 1.6.2008. The Centre assured that the States would be adequately compensated. So, the Tamil Nadu Government made a claim of ₹ 13,227.46 crores, but there is still a balance of ₹ 5,571.87 crores to be reimbursed by the Centre. I request the hon. Finance Minister to look into this and release the balance amount immediately. Sir, late Chief Minister of Tamil Nadu had continuously urged the Government of India to implement the "interlinking of the Mahanadhi-Godavari-Krishna-Pennar-Palar-Cauvery-Vaigai rivers" and further, with the Gundar river, and to divert the surplus water of the West-flowing Pamba and Achankovil rivers to Vaippar in Tamil Nadu.

Though the Special Committee, constituted for this purpose, had held 11 meetings so far, nothing concrete seems to have been done. Moreover, hon. Amma had urged the Government of India to nationalize all the Inter-State rivers. I request the Government to ponder over this point, and allocate sufficient funds for intra-linking of rivers so that the country is rid of the water problems, for all times to come.

Due to the untiring efforts of our leader, late Chief Minister of Tamil Nadu, the final order of the Cauvery Water Disputes Tribunal was notified by the Government of India in 2013. She had been urging the Centre for the early formation of the Cauvery Management Board and Cauvery Water Regulation Committee for the effective implementation of the final order of the Tribunal. Though the Centre had promised to constitute them, in a sudden turn of events, now it said that it has to come before Parliament. I would like to point out that so far, in no case, it has been done like this. So, it is neither appropriate nor fair to take a different stand now.

The farmers of the delta areas of Tamil Nadu - I am also one of the members belonging to this region- are dependent on the Cauvery waters for irrigation, and are

agitated over long delay in forming them. I request the Finance Minister to constitute them early so that the order of the Tribunal can be effectively implemented, and Tamil Nadu gets its due share of water.

Coming to the fishermen issue, as late as on 6th March, an innocent fisherman from Rameswaram was shot dead by the Sri Lankan Navy, when he along with a group of fishermen, were fishing in the Indian traditional water between Dhanushkodi and Kachchatheevu. The attack and harassment of fishermen by the Sri Lankan Navy is continuing unabated; their fishing gears and other equipments are being taken away, affecting their livelihood. Unconstitutionally, Kachchatheevu had been ceded to Sri Lanka. The two Agreements of 1972 and 1974 are not ratified by the Parliament, and so, they become invalid and unconstitutional. So, the Government of India should take steps to abrogate the Agreements and retrieve Kachchatheevu, so that traditional fishing rights of the Indian fishermen from Tamil Nadu can be restored.

Diversification of fisheries sector and comprehensive special package for this purpose were very dear to our hon. leader, late CM of Tamil Nadu. Without elaborating further on this, I request the hon. Finance Minister to sanction adequate funds for this purpose, and release them early, so that fisheries sector of Tamil Nadu can be developed, as imagined by the late CM of Tamil Nadu. As regards National Eligibility-Cum-Entrance Test, NEET, our leader, late Chief Minister hon. Amma had emphasized that introduction of NEET is a direct infringement on the rights of the State and would cause grave injustice to the students of Tamil Nadu, who are already covered by a fair and transparent admission policy, which is working very well. In this regard, Tamil Nadu also passed Tamil Nadu Admission in Professional Educational Institutions Act, 2006, which has been upheld by the Madras High Court and approved by the Supreme Court. That being so, forcing the students of Tamil Nadu to take up NEET would adversely affect the socially and economically backward students. In this regard, the Tamil Nadu Assembly unanimously passed two Bills for protecting the existing admission policy for admissions in Medical and Dental Colleges. They have been approved by the Governor of Tamil Nadu and were sent to the Central Government for obtaining the assent of the hon. President of India.

Hence, I request the Centre to kindly urge the hon. President of India, to accord sanction for these two Bills, which would go a long way in protecting the interests of the rural students of Tamil Nadu.

[Shri R. Vaithilingam]

In the Union Budget for 2015-16, the Government proposed to establish one AIIMS-like institution in Tamil Nadu. Accordingly, five sites were proposed by the State Government, including one in my place, that is, Sengipatti in Thanjavur District. It is learnt that, luckily, Sengipatti in Thanjavur District has been identified as the best-suited location for setting up this AIIMS by the Central Team.

The hon. Chief Minister of Tamil Nadu, who met hon. Prime Minister, on 27th February, 2017, also insisted on establishing AIIMS in Sengipatti of Thanjavur District. I request the Government to take immediate necessary action.

There is another long-pending demand of the people of Tamil Nadu. That is to make the ancient language of Tamil as the official language of the Government of India. Moreover, we strongly urge the Centre to declare all the languages included in the Eighth Schedule of the Constitution as Official Languages of the Government of India.

Secondly, there has been a long-standing demand of the people of Tamil Nadu to use the Tamil language in the Madras High Court. I once again, request the Centre to kindly reconsider the proposal for the use of Tamil in the High Court of Madras.

With these words, I request the hon. Finance Minister once again to allocate sufficient funds, as was demanded, immediately to tide over the finances of the State. Thank you.

SHRIMATI JHARNA DAS BAIDYA (Tripura): Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you. The Budget, presented by the Finance Minister starts with an assumption of 11.75 per cent growth in GDP for 2017-18, calculated over the revised figures of 2016-17. An analysis of the allocations under the SC/ST Sub-Plan reveals a recurring trend of under-allocation in 2017-18, wherein the SCSP comprises only 2.5 per cent and the TSP only 1.53 per cent of total allocations, which is not even the half of the mandated amount. Food, including the allocations under the National Food Security Act, kerosene and LPG subsidies have a direct impact on women. The share of these in the Budget has come down from 9.5 per cent in 2015-16 to 7.9 per cent in 2017-18. Moreover, there is no gender budget component in any of these except the LPG subsidy which is ₹ 3,200 crore. The Finance Minister also stated that the allied sector of dairy development and fisheries, which provides livelihood to a lot of women, would receive a major boost through an increased allocation of ₹ 8,000 crore. However, there is no women specific allocation in

either dairy or fisheries. The only agricultural scheme that has allocations for women in the agricultural sector is the National Food Security Mission where a nominal increase of ₹ 60 crore has been made in the gender budget, which actually accounts for less than 30 per cent of the entire allocation. Sir, ICDS Budget 2017-18, like the previous budgets, has criminally neglected India's eight crore malnourished children under six and two crore pregnant women and lactating mothers by not increasing the allocations for the Integrated Child Development Scheme. The Budget Estimates for the ICDS for 2017-18 is only ₹ 15,245.19 crore. It is even less than the budget allocation for ICDS in 2015-16, which was ₹ 15,433.09 crore and ₹ 18,108 crore in 2014-15. It is only half of the Twelfth Plan allocation for ICDS for the year 2017-18 which is ₹ 30,025 crore. The Budget boasts about the much promoted Prime Minister's announcement of the maternity benefit of ₹ 6,000 to pregnant women. This is nothing new and it has been included in the Right to Food Act. But ironically the amount earmarked for the Maternity Benefit Programme is a mere ₹ 2,700 crore which will cover only 17 per cent of the 2.6 crore live child births per year in India. These maternity benefits come as a cash transfer scheme on the condition of institutional deliveries. Sir, a dangerous move made in the Budget is the announcement by the Finance Minister to set up 'Mahila Shakti Kendra' in the Anganwadi Centres. This is nothing but putting the Anganwadi Centres at the disposal of the corporates. In the present situation half of the Anganwadi Centres are not even having basic facilities such as drinking water or their own buildings. Though there are no proposals for direct cash transfer in place of schemes like ICDS, the Economic Survey sets the direction for direct cash transfer in the name of the Universal Basic Income Scheme. The increased allocation of ₹ 2700 crore for maternity benefits comes as a cash transfer scheme on the condition of institutional deliveries. The Government has completely failed to respond on the issue of rising violence against women and the need to ensure budgetary support for survivors of violent crimes. This can be seen in the atrocious cut in the allocation of resources for the Nirbhaya fund. The revised estimate for the Nirbhaya fund in 2016-17 was ₹ 585 crores and this has been now cut to ₹ 400 crores. The total schemes for Scheduled Castes has been reduced from ₹ 294 crores to ₹ 256 crores only and the total schemes for Scheduled Tribes is brought down to only Rs. 261 crores from ₹ 307 crores in 2016-17. Only eleven new schemes for SCs and eight new schemes for STs have been introduced in 2017-18. Sir, in the Union Budget of 2017-18, the total allocation for the development of the North-East region has been increased from ₹ 32,180.08 crores to ₹ 43,244.64 crores, which is exclusive of TSP and SCSP allocations. In addition to this, a total of ₹ 716 crore

[Shrimati Jharna Das Baidya]

from the TSP and ₹ 53 crore from the SCSP has also been allocated for the Ministry of Development for North Eastern Region. But still, other than one single scheme for skill development, there has been no other new scheme introduced for the development of the North-Eastern Region. It shows that there have been major budgetary cuts for the programme related to food and public distribution, electronics and information technology, environment, forest and climate change and urban development. ...*(Time-bell rings)*... One minute, Sir. Sir, the surrender of goals like the alleviation of poverty, focusing on the special needs of women, Dalits, tribals and other deprived sections of society, through the allocation of budgetary resources for them, in favour of tax cuts for the corporate and the elite classes, exposes the real anti-people agenda of the Government. Sir, to sum up, this Budget not only ignores, but also imposes further burden on the people in the wake of demonetisation and widespread deflationary conditions. This Budget clearly upholds the interests of the market. It has no place for women. It is once again a blatant attack on the poor and the oppressed. This is a budget to appease the rich accentuating the problems of unemployment and rising inequality. Thank you.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Shri C.M. Ramesh. Not present. Shri K. T. S. Tulsi. Not present. Shri Swapan Dasgupta. Not present. Shri Abdul Wahab. Not present. Shri Tiruchi Siva.

SHRI TIRUCHI SIVA (Tamil Nadu): Thank you Mr. Vice-Chairman, Sir.

Sir, 'Incredible India', sometimes, becomes 'indelible India.' Demonetisation, which was proudly announced by the hon. Prime Minister, has not achieved its intended purpose, but its unintended consequences have devastated the lives of poor and crippled our economy.

Sir, in 2004, Dr. Manmohan Singh, demonetized some higher denomination currency. But, it gave no pains to the people. Now, the days seem to be over, but the scar is still there. Our people are used to live with miseries. The demonetization was done with some purpose —to curb black-money, to stop corruption as well as to unearth black-money. But, what happened, actually, was not that. The suffered were only the common man.

There is nothing mentioned even in the Budget speech. The hon. Finance Minister boasted so much and is proud of demonetization. But, Sir, there is no mention about

the ways, methods or means to unearth black money from other sources *i.e.,* by way of benami real estate investments, off-shore accounts and gold and precious metals. It is said, very clearly — even the hon. Finance Minister has accepted it on the floor of the House during the Question Hour — that out of total black money, only 6 per cent is in the form of cash and this 6 per cent is not with the common man. But, the person who underwent all miseries is only the common and poor.

Sir, shadow economy is prevalent in all developing economics; no country is an exception to it. For example, in the USA, 8.6 per cent of its GDP is shadow money. In China, it is 12.7 per cent. In Japan, it is 11 per cent and in India, it is 22.2 per cent. The ratio may be different; but, it is quite common and prevalent everywhere. But, no country has taken the severest step. My simple doubt is: If you say that it curtails black money and stop counterfeit currency, it is a myth. Yesterday there was a news item that the entire Chennai port was cordoned off because there was information that about ₹ 400 crores have come as counterfeit from Pakistan and they are all in ₹ 2000 denomination! How is it possible? So, when one person can print something, another person can imitate it sometime or later. Our basic doubt or query or apprehension is, when you feel black money could be stored in ₹ 500 or ₹ 1000 denomination, it would be easier with ₹ 2,000 notes. What they had stored earlier in ₹ 500 or ₹ 1,000 notes can now store double the money with ₹ 2,000 notes. But, if one says that the flow of money is not so easy is not correct. During demonetization period, people were not able to solemnize marriages in their own families. Many families could not perform marriages. It is because, Sir, only ₹ 2 lakhs was permitted to be spent on a marriage. And, looking at our culture and tradition, no marriage can be performed with ₹ 2 lakhs. So, people suffered a lot. But, at the same time, there were some marriages which celebrated pompously. And it was told that money spent was accounted. But, the point is, how they got it? When there was restriction with regard to withdrawal, when no one can withdraw more than a fixed amount in a week, how crores of rupees were spent in white money? It is a very big question. So, we expected that, at least, the hon. Finance Minister, in his Budget, would come out with a fact as to how much black money has been unearthed through demonetization. Sir, 85 per cent of currency is of higher denomination. When higher denomination was demonetized in 1978, it was around 1-2 per cent. Sir, ₹ 1,000 note was unreachable for the common man. But, today, 85 per cent of currency is in the form of ₹ 500 and ₹ 1,000 notes. Even a coolie or labourer or farm worker has got ₹ 500 and ₹ 1,000 note. And you say that black money

[Shri Tiruchi Siva]

is with him! For example, a tea stall owner who opens his shop early in the morning and closes it at night saves some money every day. He preserves that money for his daughter's marriage. He cannot go to a bank and deposit it. He keeps that money in his box or keeps it at his house. Over the years, it gets multiplied up to ₹ 2 lakhs or ₹ 3 lakhs or ₹ 5 lakhs. Then, he is ready for marriage. And, all of a sudden you demonetize money and when he carries that money to bank, they ask, 'what is the source?' Every person can deposit only up to ₹ 2.5 lakh', that is what they said, and even that will be probed into. This person saved five rupees, ten rupees, or, hundred rupees everyday and it got multiplied over years together. He saved it like anything. He did not sleep at all. He kept it under his head. He was keeping it at home. All of a sudden, demonetisation came. When he took it to the bank, it was considered as black money. But, actually, the black money holders are very safe. They had already shifted their money to the safest place. Everyone knows that. That is what I said. What are the methods and means you have in hand to unearth the black money which is in offshore accounts, which is in the form of real estates, which is in the form of gold and precious metals, mining and everything. It is a very simple thing. For example, if you go to a town or a place, find a house unoccupied, not renovated and it has been lying there for quite a long time in a posh area, it is black money. If you find hundreds of acres on a highway unutilised, or, nothing has been constructed on it, it is black money. What is the proposal the Government is having to deal with all these things? We have seen how people were waiting for their money! There were long queues outside the ATMs; no one cared about that. So many people, more than 100, died. The people who get pension every month, who have been deserted by their children and who live their life by way of that pension, were getting the pension but they were not able to withdraw that money. They were forced to stand in the long queues. They fainted, they starved out of hunger and some people even died. % No one cared about them. My basic doubt is this, Sir. When you switch over to a new currency, of a higher denomination, shouldn't you apply your mind that the currency should fit into the already existing ATM machines? The existing ATMs were not in a position to operate with the new currency because the size was different. So, everything was amiss. Sir, the intention may be good, but the implementation process was very, very bad. Now, the people have become used to that. That is what I said in the beginning itself. If the bus fare is hiked, the people will be shouting at it, but they will be paying for it. If the petrol price is hiked, they will be feeling for it, but they will be paying for it. Like that, for the past three months, they have been

accustomed to demonetisation and they are now used to new 2,000 rupee notes. You know what the value of ₹ 100 in those days was. We were not able to shell out to anyone. My another very basic doubt is this. An ordinary vendor on a roadside does selling of at least ₹ 2,000 - ₹ 3,000 per day. Suppose his transaction is of ₹ 3,000/-. His profit will be ₹ 500/-. He eats with that and he spends with that. But, now, when you bring in the cashless society, just imagine if that comes into operation, these ₹ 3,000/- will be transacted by way of card or something like that. It will be accounted. Per month, what will be his income? It will come to about ₹ 1,00,000, and per year, it will be ₹ 12,00,000/-. What will be his tax slab? It will be the uppermost slab. So, a person who earns only ₹ 500/- per day, and living on it, his income will be shown as ₹ 3,000/- per day, as a result, his income per month will be ₹ 1,00,000/-; for a year, it will be ₹ 12,00,000/-, and he will come under the uppermost slab. He will be required to pay 30 per cent tax, means he will have to pay ₹ 4,00,000/- as income tax and he would have nothing at all with him. What he earned, he has already spent. These are all very basic things which anybody should have speculated. You are worried about black money as every one other is, but what is the way out of it. That is what we are again and again asking. I ask it in another way. As I said, when ₹ 500/- and ₹ 1,000/- could increase black money, why not ₹ 2,000/-? For example, the US, which is considered to be the richest country in the world, its highest denomination is only 100 dollars. The Britain whose finances or wealth are equivalent to half of the world, they say, the highest denomination is 50 pounds. In other European countries, it is 50 Euros. So, they have 100 Dollars, 50 Pounds and 50 Euros whereas you are shifting from ₹ 500, or ₹ 1,000 to ₹ 2,000/-. I think these are not the ways and means. So, the country has gone through a very bad thing and, therefore, at least, in the Budget Speech, we expected the Finance Minister to say how much money has been unearthed. But nothing has come out. If at all so much money was in floating, people were using it, how much was deposited? All that money that has not been deposited, that is black money. So, those people who were not able to deposit it would have done it in some other manner. How much money has been deposited, how much was in use, how much money is black money, no, Sir, no such information from the Finance Minister was given even in his Budget Speech. Everyone has spoken about demonetization and I have to also say something about it because everyone suffered. Even we went to the Bank in the Parliament House. They said, you will be getting only four thousand rupees and that four thousand rupees was for one week. The next week, I had to go there again to get four thousand rupees. It is highly ridiculous. We cannot just live on four thousand rupees a week, and they expected the people of this country to get along. They said, 'It is a short-term pain

[Shri Tiruchi Siva]

and long-term gain.' No, Sir. There is no short-term pain. It is a long-term pain and not even short-term gain. The Government can be proud of it. Of course, your measures are good, your intention is good, but the implementation part spoiled everything else. So, in that way, the country has gone through a very, very bad period and the people went through very miserable days and now they are getting out of it. I am afraid, again, even the last man would be suffering in the coming days; and everyone will be accountable.

Sir, the Internet connectivity is only 16.1 per cent in this country. Only 47 per cent of the people are having bank accounts but you want them to enter into cashless society. They don't know what is Internet. They don't know how to operate a mobile phone like that. So many people are still left out with it. I may have two phones, another one may have three but many people do not have mobile phones. They do not ABC, they do not know alphabets, they do not know numbers, but you expect them to transact cash by way of cashless society! Sir, we are living in India. We have to legislate laws and we have to bring out schemes suited to our people, not to Netherlands, not to other countries which have succeeded. We cannot compare them. There are some countries where there are hundred per cent taxpayers. But, here, in our country, it is not so. People are uneducated. People are not updated with Internet literacy. They do not know what is mobile, what is bank account and all that, but you expect them to come into cashless society! Sir, it is too hasty a decision. It has to go step-by-step. All of a sudden, one fine night, it was declared that these currencies would not be valuable and it was demonetized and the whole country went into very bad days. My only observation is that even after that if you have achieved by way of getting some black money through this, you should have told that in the Budget which is not there.

Sir, along with that, I have two-three very, very important points. Another is about public sector undertakings. The Government is very keen in disinvesting the public sector. Sir, Pandit Jawaharlal Nehru while inaugurating the Bhakra Nangal Dam had said, 'The Public Sector Undertakings are the temples of our economy.' Sir, it is not only an organization which generates employment, it also helps our economy. You know very well, Sir. We have been in various Committees and we have also been studying the functioning of the Public Sector Undertakings. If the private sector is earning something, it is the wealth of one person but if the public sector is earning something, it is the wealth of the country. If, at all, the public sectors are failing somewhere, we have to go into its reasons and plug the loopholes, whereas, we are trying to wind it up. For example, take

4.00 P.M.

the Salem Steel Plant in Tamil Nadu which had been installed there after a lot of pains and strains in those days when the DMK was in power and Mrs. Gandhi was in power. But now it is about to the disinvested or closed. Sir, it has been spread out in four thousand acres of land and it has got so much of worthy minerals. If you are selling it out, any private person will take it off. The Government money will go to the private person. That money will also be spent by the Government for various schemes. So, I urge, Sir, just kindly look into the restructuring and revival of Public Sector Units, and resilience of the Public Sector Units alone will save the economy of the country. Kindly don't go into disinvestment.

Secondly, the scholarship being given by the Ministry of Social Justice and Empowerment to students of the *Adi Dravidar,* the Scheduled Castes is very meagre. The arrears to be paid to those students have already piled up too much. It has accumulated and they are not being paid. Even in this Budget, we claim that we are for the development of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes and yet, the scholarship amount extended to them by the Government is very meagre. It won't meet their needs. That also needs to be looked into.

Sir, third and most important, the hon. Finance Minister, in his Budget Speech in February, said, "Steps will be taken to promote contract farming in the country. A model law on contract farming would be prepared and circulated among States for adoption for better price realization and reduction of post harvest losses." The system of contract farming has historical references, such as the infamous contract system enforced upon the indigo plantation farmers in East India during the British Rule. A recent example is the United States of America where corporate penetration in agriculture is highly advanced. The practice of contract farming reduces farm income, increases the prices for consumers and, at the same time, increases the margin for procurement firms. So, individuals would be benefited while farmers would be victimized. Also, the consumers would be penalized. This is a system that has grossly reduced the independence of farmers. It has put them under immense pressure and under the total control of the corporations, which not only decide the quantum of production but also the price of the product that is being procured. All these things show that it has gone from the hands of the farmers to those of the private concerns. They would decide which crop is to be produced and they would advise more mechanization. More mechanization would mean more loss of employment because it would need only lesser people for working in the farms. Increased mechanization,

[Shri Tiruchi Siva]

increased use of chemical fertilizers, pesticides and more and more GM seeds would ultimately spoil agriculture in our country.

SHRI OSCAR FERNANDES (Karnataka): Ultimately, the farmers would become landless.

SHRI TIRUCHI SIVA: Yes, Sir. ...*(Time-bell rings)*... Sir, I would conclude with this.

India is basically an agrarian country. We should not forget that. I have said repeatedly in this House that during the period of recession, in 2008, which emerged from the US and the impact of which was felt across European and other countries, India withstood the effects only because of two reasons — one, the agricultural sector, that was selfsufficient and two, public sector undertakings. But you are trying to kill both.

SHRI JAIRAM RAMESH (Karnataka): Also nationalization of banks.

SHRI TIRUCHI SIVA: Yes, Sir. Why are you trying to break all those things that form the backbone of the economy of our country? The farmers should not be made to suffer. What I would suggest is, instead of going in for contract farming and encouraging corporates in agriculture, you may find other ways. Even the other day our esteemed senior colleague, Shri Oscar Fernandes, said that there is a shortfall in production. Find out some means to encourage the traditional agricultural methods and to save our farmers. Instead of thinking on those lines, you are thinking the other way; you are planning to make our agriculturists slaves to some foreign country. This should not happen. It would be the worst day for this country if that happens. Kindly reconsider contract farming. All those things that you have done to the public sector undertakings and the agricultural sector are not encouraging at all. Demonetization has affected us a lot. I have also said that the scholarship amount allocated to the Scheduled Castes students should be further increased. Only then the country would move in the right direction. These are only my suggestions and observations on this Budget. We are equally concerned as you are. You are in the Government. We are not in the Government, but we are all concerned about the welfare of the people.

Sir, farmers from Tamil Nadu have been on strike at the *Jantar Mantar* for the past seven days. They are half naked. They are starving. They are trying to commit suicide.

Since 2014, 5,000 farmers have committed suicide in this country. Contract farming would lead to, as the hon. Member here said, farmers becoming landless and everyone would be forced to commit suicide. They do not know any other job. So, our farmers would be let down and the country would fall into — sorry to say — doom. That should not happen. Kindly take care of the agriculturists, the public sector undertakings and the Scheduled Caste students.

THE VICE-CHAIRMAN (DR. SATYANARAYAN JATIYA): Now, Shri Kapil Sibal; not present. Prof. M.V. Rajeev Gowda.

PROF. M.V. RAJEEV GOWDA (Karnataka): Sir, in this year's Budget Speech, the Finance Minister made a departure from the usual practice. He did not focus only on money-related issues and schemes of various sorts, he laid emphasis also on electoral reforms. Now, all of us who are interested in improving the political system applaud the intent of the Finance Minister in bringing up the electoral reforms' agenda. My focus is going to be on the electoral reforms' agenda which is very close to my heart.

Let me first begin by addressing two of the key initiatives that Mr. Jaitley brought forward in his Budget Speech. The first one focused on this innovation called 'Electoral Bonds'. The logic of Electoral Bonds was that he wants to infuse white money contributions into the political system. And he said, 'Through Electoral Bonds which can only be purchased in banks, you will have to use cheques or other white money in order to purchase these Electoral Bonds.' Sir, in the recent example of demonetization and its aftermath, we saw a lot of black money being converted to white in the banking system. Sir, it is not at all clear to me how Mr. Jaitley's hope that black money will not enter through the Electoral Bonds' system will actually be fulfilled. Needless to say, that is a measure that aims to address one aspect of the problem, that of black money entering the political system.

But there is another part of the Electoral Bonds' proposal that has a flaw in it, and that is the anonymity that Mr. Jaitley wants to ensure for Electoral Bonds. His explanation has been that people as well as corporates have the opportunity to contribute through cheques but nobody is really doing that in any significant way. Well, that is really because corporate and individuals do not want to be identified as contributors because they fear retaliation from various other political parties if some other party comes to power. Sir, that is all very well. But fundamentally there is a phrase that we need to pay attention to. That phrase is called 'follow the money'. Any time there is a political contribution, it is

[Prof. M.V. Rajeev Gowda]

hard to believe that it is only for the public good and for the country; especially corporate contributions often have some agenda or some policy goal attached to that particular contribution. If you make these contributions anonymous, then our ability to find out who contributed to what, who influenced what policy outcome, that will not be available to us. That transparency that currently exists will be replaced by opacity and that is not a progressive measure; it is a regressive measure.

Let this data which will be available with the banks also be available maybe with the Election Commission of India. Maybe, it is not appropriate to release it to every political party, but there has to be some way of tracking who contributed to whom and who influenced what political outcome.

Another point that Mr. Jaitley made was that he would lower the amount that can be contributed by individuals anonymously without having to declare who the contributor is from ₹ 20,000 to ₹ 2,000. Now, the reality what every one accepts, is that when the contribution is below ₹ 20,000, that quite often provides a loophole for people to convert black money again into white basically by declaring contributions of less than ₹ 20,000. Now, if you look at political parties across the spectrum, 65 per cent to 70 per cent of political parties' funds are raised in the small donations in cash and the contributors are not declared. Now, the limit comes down to ₹ 2,000. Will this have any different impact? All it means is that the same political parties will have to fill out more and more names, put in a little more effort and the end result is the same. Black money will continue to enter the system and we will not be improving things in any significant manner.

So, if you look at these two major initiatives that are mentioned in this Budget, they are intended well, but they don't deliver the results that are required. Sir, if you want electoral reforms, if you want to reform the political system, you have to go back and look at the initiatives that had been introduced at various times. For example, late Shri Rajiv Gandhi introduced the anti-defection law, which aimed at cleaning up the political system and some of the flaws that had emerged. Now, much later, decades later, each rule and regulation may have its own counter-productive effects and it is time for us to re-examine these laws and bring about change.

Sir, let us look at a couple of these kinds of counter-productive laws. There is a law which says that no political candidate can spend more than ₹ 70 lakh for a Lok Sabha election. Political parties can spend how much they want – that is a big loophole – but

individual candidates cannot spend more than ₹ 70 lakhs. What is the effect of this law? We have this cap because we want to ensure some kind of a level-playing field, but the truth of the matter is that legitimate election expenses go much beyond that. So, what this cap on expenditure has done is that it has driven expenses underground. When you drive expenses underground, what is the result? Only those, who are able to spend black money, who have the networks to go out there and use black money in the electoral process, will benefit. Clean and honest politicians do not stand a chance. And, this has become the equilibrium today where political parties select candidates by seeing how fat their wallets are, how much cash they have, how much black money they are capable of spending. So, this is a kind of a counter-productive rule that needs to be thrown out.

Former Prime Minister, Mr. Vajpayee, mentioned that point. He said, "Every MP begins his career with an untrue statement by filing incorrect accounts of the election expenditure." Sir, any law, which forces us to do something wrong, should not be on the books. Get rid of that. Let expenditure come out in the open, let sunlight be the best disinfectant in terms of cleaning the political system.

Sir, along with this, I want to dwell, in much more detail, on a subject that should have been there in the Finance Minister's Budget Speech. The Budget is about taxing and spending, about allocating resources to initiatives that will make a difference, and there is one initiative that has not been seized by the Finance Minister in the context of electoral reforms. That is State funding or public funding of elections. Sir, when you think about that, this is something that we have been talking about for quite a while. This was an opportunity for the Finance Minister to provide resources for something like that.

Why do we need State funding? If you think about electoral reform, we have many goals. We want to encourage competition. For a healthy democracy, there needs to be competitive elections, there needs to be political parties who have the resources to compete in the elections and to run and flourish and agitate in between the elections. You need political candidates who are not beholden to corporate interests or to anybody else, who are able to raise funds from various people.

And, if you ask the people of India, "Do you want to improve the electoral outcomes, or, do you want to clean up the political system?", everyone will say, "Yes". If you ask them, "Are you willing to contribute money for that purpose?", they will demur, they will say, "Well, let somebody else contribute who is richer than us." Sir, when everybody wants something but nobody is willing to contribute, we use the taxation system to

[Prof. M.V. Rajeev Gowda]

provide those goods because that is what people want, but we do not know how to collect those resources. So, when we take taxes and allocate them to State funding, then we should actually call it public funding, so that the people realize that it is their money which is going in to clean up the political system and to ensure a competitive electoral marketplace. Why do you need a certain amount of spending? People will say that this is going to only add more money to run the election expenses, but the fact of the matter is that people can spend crores and crores, but to win an election, all the amount of money that you spend is not enough. You win on the basis of a variety of factors. But the most important thing is that to be competitive, you need a threshold level of expenditure. You need to spend a certain amount of money in order to be seen as a serious candidate, and that amount of money should be contributed by the public exchequer through public or State funding of elections.

Now, how would you go about doing this? Why is this justified? We want a level-playing field. Typically, the ruling parties are the ones that are able to raise more resources. So, what happens to the opposition afterwards? This is something that today, we are in the opposition, and by the next election, I am confident that the other side will be in the opposition. Basically, the point is that for the system to improve, we all need to come together and ensure that we raise resources for the political parties across the board. The philosopher, John Rawls talks about a system which is not just about a level-playing field. He says you also need to provide disadvantaged people in a particular system with additional opportunities. Today the person who is disadvantaged in the political system is the honest politician. They are the ones who do not have a chance when every party is looking for winnability measured by the size of the wallet. So, we need to ensure that candidates and parties raise the resources in a clean and legal manner.

How would you do this? There are a variety of proposals that have emerged in recent times. The former Election Commissioner, Mr. Qureshi; the activist and politician, Mr. Yogendra Yadav, and, many others have come up with their proposals. Let me give you mine, prepared along with Mr. Varun Santosh, which is focused on two aspects. For every vote the political party has got in the last elections, you allocate hundred rupees. This will go to the political party – half of it to the Central Party and half of it to the constituency-level bank account – so that this can be used over the next five years for

political activities. Thus, good social workers, who have done a great job but are not rich and who can still be chosen as candidates. That is one half of this money. The other half should be used to incentivize parties and candidates, individuals as well, including independents, to be able to raise money from the public and get some kind of a matching grant. This way, you are incentivizing people to go out there and demonstrate the kind of support that needs to be there to make candidates and parties viable.

Let me go back to the time of Mahatma Gandhi, who used to collect huge amounts of resources from the 4-anna membership of the Congress and also from the contributions by the public. He was a master fund-raiser because people believed in him, his leadership, his cause and the Congress Party. That is the kind of measures that we need to take. We need to give individual candidates and political parties an opportunity to raise funds through open and clean contributions which are tagged with Aadhaar number, PAN card number or something like that, so that there is an incentive to go out there and raise clean money. Even individuals and independents should be given this opportunity. You can allot certain amount of resources per constituency, and let that be divided according to how much has been raised.

When you do all this, many of the other objections, which the activists have against the political parties that we do not come under the Right to Information Act (RTI), we do not allow ourselves to be audited properly, etc., can go because once you receive State funding in some significant manner, then, political parties will have to allow for audits, allow for RTIs, at least, when it comes to the financial side of how they go about their business.

There is one more issue, which I want to mention. The media needs to be audited. So, all advertisements on television, on social media and in print media need to be disclosed and audited by an independent source, because there is a lot of paid news and other kinds of media malpractices which are also affecting the political system.

Sir, how much will this all cost? It will cost much less than the MPLAD amount which has been allocated and which we all use in our constituencies. And, if you say that this is a lot of money, how can we afford it, I would say, please think of the larger goal. Why Mr. Jaitley is talking about electoral reforms is because we want to clean up the political system, we want a democracy that we can be proud of. But, for that, we need to be able to invest in the legal and legitimate cost of democracy, the cost of campaigning, the cost of running a political party, and the cost of even being a political activist. Sir, these are the things, which are very, very important.

[Prof. M.V. Rajeev Gowda]

We need transparency, we need the ability to go out there and do whatever it takes to ensure that our democracy flourishes. Remember, this is an economy — thanks to the seventy years of build-up by Congress and other Governments — which is now the third-largest economy in the world in terms of Purchasing Power Parity (PPP). We are a multi-trillion dollar economy. If a multi-trillion dollar economy, one of the top economies in the world, cannot afford to put aside some resources for public funding, to cleanse the system, then, that would be a shame on us. Let us hope that the Finance Minister will respond to what I have offered, and, will also undertake the electoral reforms proposals that he has made, and ensure that we are all together in this huge and very, very crucial effort to clean up our political system so that the people of India can be proud of all of us here in Parliament, in every other House and in every other political party, as we take the nation forward in the 21st century. Thank you, Sir.

श्री महेश पोद्दार (झारखंड): उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं बजट प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह दोहराना चाहूँगा कि बजट के पीछे की मूल भावना है- "सबका साथ, सबका विकास", जो सिर्फ नारा ही नहीं है, बल्कि एक आंदोलन है। भविष्य के लिए बदलाव की जो भी जरूरत थी, वह बदलाव बजट प्रस्ताव में किया गया। पिछले दिनों चुनाव के परिणामों में मिले अपार जनसमर्थन के बाद तो यह समर्थन हमारा एक औपचारिकता मात्र है, लेकिन यदि यह महसूस किया गया है कि बजट में बदलाव, प्रक्रिया में बदलाव आवश्यक है, तो वह किया गया, क्योंकि जो समय से बदलाव करे, वही सिकंदर।

आजादी के बाद प्रधान मंत्री जी की अन्न-त्याग की बात हमें याद आती है और उसके बाद स्वेच्छा से गैस सिलेंडर की सब्सिडी give up करने की बात याद आती है, जब इस देश के एक करोड़ से अधिक लोगों ने स्वेच्छा से अपने देश के लिए, अपने देश के गरीबों के लिए कुछ त्याग किया। जनसाधारण का स्वेच्छा से ऐसा समर्थन और जनभावना की शक्ति का प्रतिलक्षण यह दिखाता है कि इस जनशक्ति ने सामूहिक रूप से बड़े नोटों की बंदी के निर्णय को अभूतपूर्व समर्थन अनुशासन के रूप में भी दिया।

महोदय, बजट प्रस्ताव मात्र आमद-खर्च का हिसाब नहीं, बल्कि पारदर्शिता के साथ राज्यों को भी साथ लेकर दृढ़ता से अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ने की एक प्रक्रिया है। हमारे साथी, माननीय हरिवंश जी, जिन्हें मैं 20-25 वर्षों से पढ़ता आया हूँ, सुनता आया हूँ, उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही कि यह बात राष्ट्रीय हित में है कि किसी मुद्दे पर मात्र विरोध के लिए हम विरोध न करें। अच्छा हुआ कि उन्होंने सरकार को भी यह याद दिलाया कि वादा तो आपने किया है, इसे निभाना पड़ेगा। हम भी मानते हैं कि हम जो वादा करते हैं, उसी दिशा में हम काम करते हैं और हमारा यह वादा मात्र वादा नहीं, बल्कि हमारा एक लक्ष्य है।

महोदय, उन्होंने तथा अन्य कई वक्ताओं ने कई समस्याएँ बताईं। सरकार के सामने आजादी के बाद से लेकर अब तक की बहुत सारी समस्याएँ और बहुत सारी बातें बताई गईं। मैंने एक नये सदस्य के तौर पर यह महसूस किया कि क्या हमारी सरकार ही इन सारी चीज़ों के लिए जिम्मेवार है? बंगला में एक कहावत है- "जोतो दोष, नन्दू घोष।" यानी, जितना दोष है, वह सारा नन्दू घोष का है। तो क्या सारा दोष मोदी घोष का है? मोदी घोष तो पिछले दो-ढाई साल से ही सरकार चला रहे हैं। यदि वर्ष 2011 के सर्वे की बात आई कि देश में 26 लाख सूखे शौचालय चल रहे हैं, तो क्या इसके लिए भी यही मोदी घोष जिम्मेवार हैं? क्या हम इस चीज़ को नहीं देख सकते कि उसके बाद में इनके कार्यक्रम में क्या सुधार आए-गए, आज के दिन में क्या स्थिति है, इसकी चर्चा हम क्यों नहीं करते? इस सरकार के regime में बातें बिगड़ीं या सुधरीं, इसके बारे में हम चर्चा क्यों नहीं करते?

महोदय, छोटी-छोटी बातें बड़े परिणाम देंगी। छूट गईं छोटी-छोटी बातों की भी शुरुआत कहीं न कहीं करनी पड़ेगी। तीन राज्यों ने ODF की घोषणा की है और अन्य राज्य करने वाले हैं। आज जब हम सफाई की बात कर रहे हैं, तो हम आर्थिक जगत की सफाई की बात क्यों नहीं करें, उसकी चर्चा क्यों नहीं करें, उसकी कमी को क्यों नहीं महसूस करें? पंडित दीनदयाल जी की जन्म-शताब्दी पर सबका साथ, जो बहुत पीछे छूट गए, उनको भी आगे लाने के लिए, "गरीब कल्याण वर्ष", एक इंसान को घर, बिजली, पीने के लिए सेफ वॉटर, आधुनिक ईंधन, रोजगार, सस्ती दवाई और अन्य योजनाएँ सीधी पहुंच रही हैं। इस सीधी पहुँचने की प्रक्रिया में तेजी से वृद्धि हो रही है, कमी नहीं हो रही है और उसका लाभ भी दिख रहा है। एक तरफ जहाँ सरकार को कुछ पैसे बच रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ beneficiaries को भी पैसे बच रहे हैं, क्योंकि बीच में कटौती हो जाती थी, जो हम सब जानते हैं, उसमें भी कटौती हो रही है, तो उससे beneficiaries को भी फायदा हो रहा है और सरकार को भी फायदा हो रहा है।

महोदय, किसानों की आत्महत्या की चर्चा तो हम बहुत समय से सुनते आए हैं, लेकिन उसके निराकरण के लिए कई प्रयास किए गए, फिर भी वे पूरे नहीं पड़ रहे थे। इस सरकार ने इस बजट प्रस्ताव में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना की एक नए रूप में लिया गया है, जिसमें प्वाइंट टू प्वाइंट शुरू से लेकर अंत तक, जब तक वह माल बिक न जाए, अंत तक की एक कॉम्प्रिहेंसिव समुचित सुरक्षा प्रदान करने की बात की गई है। हमारे पूर्व वक्ताओं ने कहा कि जो-जो कमियां थीं, उनको धीरे-धीरे एड्रेस किया गया है। मुझे ऐसा विश्वास है कि आने वाले समय में जैसे-जैसे यह योजना सफल होगी, लागू होगी, पॉपुलर होगी, वैसे-वैसे सुइसाइड के केस कम होते जाएंगे। यह एक जो दुखद शर्मनाक सामाजिक, आर्थिक विफलता थी, उससे हम मुक्ति पाएंगे।

महोदय, इस सरकार ने "एक्ट ईस्ट" का उल्लेख किया है। हम सब जानते हैं कि देश के विभिन्न भागों में थोड़ी आर्थिक समानताओं की कमी महसूस हो रही है। मेरा झारखंड देश की ऊर्जा क्षेत्र की जरूरत को पूरा करता है। पर ऊर्जा की उपलब्धता के मामले में हम देश के अन्य राज्यों से बहुत पीछे हैं। "प्रधान मंत्री ऊर्जा गंगा योजना" द्वारा नेचुरल गैस हमारे राज्य में लाया जाएगा। मैंने पढ़ा कि ओडिशा में काम शुरू भी हो गया है और बहुत जल्दी यह झारखंड तक पहुंचेगा और इसके बाद हमारे फर्टिलाजर प्लांट्स भी चालू होंगे। ऊर्जा की जरूरत भी कम होगी। तो यह इसलिए भी सराहनीय है कि

[श्री महेश पोद्दार]

यह संघीय ढांचे को मजबूत करता है,सारे देश का हर भाग समान रूप से विकसित हो, यह इसकी आवश्यकता है। झारखंड तो पिछड़ा ही है, लेकिन महोदय, झारखंड का एक अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है, संथाल परगना। संथाल परगना में साहबगंज में बंदरगाह बनने की बात की गई है। महोदय, लोगों की बुझी आंखों में चमक दिखनी शुरू हो गई है। संथाल परगना के लोगों ने कल्पना नहीं की थी कि यहां ऐसा कुछ चमत्कार होने वाला है। लेकिन इस बजट के प्रस्ताव के बाद में वहां के लोगों की आंखों में चमक दिखनी शुरू हुई थी। उसी संथाल परगना क्षेत्र में हमने प्रस्ताव किया है और वित्त मंत्री जी ने घोषणा की है कि एम्स बनाया जाएगा। यह सब कुछ अभूतपूर्व हो रहा है। महोदय, उससे बड़ी बात है कि लोगों के मन की बजट की घोषणाओं को मात्र घोषणा नहीं माना जा रहा है, बल्कि इन्हें एक समयबद्ध कमिटमेंट माना जा रहा है। यह बहुत बड़ी बात है कि जनता का विश्वास है, ये जो घोषणाएं हो रही हैं, वे पूरी होंगी।

महोदय, रेल के मामले में हमने देखा कि बजट प्रस्ताव में घोषणाएं नहीं हुईं। लेकिन कहीं पर भी इस पर बहुत जोर से क्रिटिसिज्म नहीं हुआ, क्योंकि उनको विश्वास है कि जो घोषणाएं की गई हैं, जैसे अभी कुछ दिन पहले रांची से टोरी तक बहुत दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में रेलवे लाइन का विस्तार हुआ और वह चालू हुई। जो योजनाएं वर्षों से, दशकों से पैंडिंग चल रही थीं, वे अभी कम्प्लीट हुईं और वहां यात्रियों के आवागमन की सुविधा चालू हुई है।

महोदय, चित्रकार कल्पना करता है, उसे उकारता है, यदा-कदा सुधारता है और फिर कूची में अनेकों रंग भरता है और तब अपेक्षित चित्र को पूरा करता है। एक चित्र को पूरा करने के बाद में वह फिर दूसरे चित्र में लग जाता है। लम्बे अंतराल के बाद देश ने भाजपा और उनके सहयोगियों को नरेन्द्र भाई मोदी के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत की सरकार बनाकर मां भारती के उज्जवल चित्र को पूरा करने का दायित्व सौंपा है और वे बखूबी उसको पूरा कर रहे हैं। माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट कई मायनों में अलग रंग का है। करीब महीने भर पूर्व रेल बजट का समायोजन, आउटकम बजट की अवधारणा जैसे रंग अलग से दीखते हैं, उम्मीद बंधाते हैं। इकोनॉमी के मामले में विश्व के प्रसिद्ध अखबार "वॉल स्ट्रीट जनरल" ने यह कहा कि इस बजट की सराहना इसलिए की जानी चाहिए कि उन्होंने वह कुछ नहीं किया जिसकी अपेक्षा की जाती थी। फिर उसने आगे कहा कि 5 राज्यों के चुनाव सिर पर थे, उसके बाद भी इस बजट में रेवड़ियां नहीं बांटी गईं और चुनाव में मतदाताओं को लुभाने के लिए लोकप्रिय और सस्ते उपाय नहीं किए गए। बल्कि वित्त मंत्री जी ने रोड, रेल इत्यादि में पूंजीगत निवेश करना उचित समझा - 20 प्रतिशत से अधिक पूंजीगत निवेश, जिसके दीर्घकालीन परिणाम होंगे, जिससे रोजगार के अवसर निर्मित होंगे। इसलिए बजट की तारीफ की जानी चाहिए। अगर कोई इसे रंगीन चश्मे से ही देखेगा तो बात अलग है, उसका नज़रिया अलग होता ही, लेकिन इसी क्रम में हम देख रहे हैं कि बजट वाले दिन सेंसेक्स स्टॉक इंडेक्स 1.76 परसेंट बढ़ा, जो सन् 2005 के बाद अधिकतम है। इसमें कोई मतभेद नहीं कि भारत की अर्थव्यवस्था विश्व की सबसे तेज़ बढ़ने वाली व्यवस्था है और वह बरकरार है। महोदय, इस बजट में चुनाव के बावजूद सरकार द्वारा तत्कालीन

लोकप्रियता के लोभ से बचते हुए लोक लुभावने वायदे नहीं किए गए। सरकार द्वारा नोटबंदी के बावजूद बजट घाटा 3.5 प्रतिशत की जगह जीडीपी का 3.2 परसेंट होने की संभावना व्यक्त की गयी है। वर्तमान स्थिति में जो देश के लिए अप्रत्याशित है, लेकिन देश हित में है, उसके संबंध में सरकार द्वारा दृढ़ता से निर्णय लिए गए। सरकार ने digital economy को बढ़ाने की बात कही है, लेकिन साथ ही साथ Cyber Security की दिशा में Computer Emergency Resesponse Team की व्यवस्था का भी प्रस्ताव है। Information Technology, जो एक नयी economy है, रोज़गार उन्मुख है, अधिक से अधिक लोगों को सीधे रोज़गार देने में सक्षम है, उसमें भी उदारता दिखायी गयी है।

महोदय, बजट में भारत की ताकत, उसकी युवा शक्ति को सक्षम बनाने हेतु 100 Information Skill Centres के माध्यम से, Innovation Fund के माध्यम से, Startup Projects के माध्यम से और अन्य माध्यमों से शिक्षित लोगों को रोज़गार में लगाया जाएगा। सरकार ने disinvestment के लिए भी प्रस्ताव दिए हैं, लेकिन ये प्रस्ताव स्वामित्व को निजी हाथों में देने के लिए नहीं, मात्र निजी निवेश के लिए दिए गए हैं - स्वामित्व सार्वजनिक क्षेत्र में ही रहेगा। हम सब जानते हैं कि कई कारणों से निजी पूंजी निवेश में दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन निजी पूंजी निवेश में कठिनाई के बावजूद विकास दर को बनाए रखना हमारी आर्थिक ताकत का प्रदर्शन करता है।

महोदय, रोटी, कपड़ा और मकान सरकार के लिए चुनावी वायदा नहीं, बल्कि साध्य है, लक्ष्य है, वायदा है। रोज़गार, स्वरोज़गार, मनरेगा में 48,000 करोड़ का आबंटन तथा अन्य बहुत से अभूतपूर्व प्रावधान इस बजट में किए गए हैं। घरों के मामले में National Housing द्वारा 20,000 करोड़ से अधिक की राशि, हर तबके के लिए घर के लिए अनुदान की योजना और यदि हम आंकड़े देखें तो अनुमोदित घरों की संख्या जहां 2013-14 में 3,931 थी, अब 2016-17 में 20,268 हो गयी है। अब केन्द्रीय सहायता 97 करोड़ से बढ़कर 491 करोड़ हो गयी है। यह दिखाता है कि हमारी प्राथमिकता किस तरह से बढ़ रही हैं।

महोदय, यह जानकर और पढ़कर खुशी भी होती है और दुख भी होता है कि आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी हम अखबार में पढ़ते हैं कि फलां गांव में बिजली आयी। पता नहीं, इसके लिए हम किसे जिम्मेदार ठहराएं या किसी को जिम्मेदार ठहराने की आवश्यकता है अथवा नहीं या जिनका दायित्व था, वे अपने दायित्व को समझते हैं या नहीं, अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं या नहीं, लेकिन हकीकत यह है कि आज भी गांवों का विद्युतीकरण चालू है और बहुत तेजी से चालू है और सरकार का लक्ष्य है कि सन् 2019 तक हर गांव का विद्युतीकरण हो जाए। वर्षों से शिथिल मशीनरी अब तेजी से लक्ष्य की ओर बढ़ रही है, गांव के गांव एलईडी बल्क से रोशन हो रहे हैं।

इसी प्रकार "प्रधान मंत्री उज्जवला योजना" है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि गरीबों के घरों में भी गैस के सिलेंडर आएंगे। हमारे झारखंड जैसे राज्य, जहां लोग ईंधन के लिए जंगल के पेड़ों की कटायी करते थे, वहां पर यह योजना प्रकृति को, environment को बचाने में मदद कर रही है।

महोदय, अगर हम आयकर की बात करें तो इतना तो तय है कि हर करदाता को साढ़े बारह

[श्री महेश पोद्दार]

हज़ार रुपए वार्षिक लाभ तो होगा ही, लेकिन यह सरकार अपने टैक्स के आधार को बढ़ाने के लिए और tax compliance को बढ़ाने के लिए कटिबद्ध है। उपसभापति महोदय, यह भी एक तथ्य है कि समाज का एक वर्ग काले धन में लेन-देन करता है। इसकी ओर सबका ध्यान है, लेकिन यह भी एक तथ्य है कि इसी समाज का एक वर्ग काले धन से सिर्फ लेन-लेन करता हे, लेन-देन नहीं करता है। वह लेना जानता है, वह देना नहीं जानता है। ऐसे लोगों तक पहुंचना और उन्हें टैक्स के दायरे में लाना ज्यादा मुश्किल है और सरकार के लिए यह एक चुनौती होगी। मुझे विश्वास है कि यह सरकार उन्हें भी नकेल पहनाएगी। अभी थोड़ी देर पहले हमारे नरेश भाई ने कहा कि हवा का जोर एक-सा रहता नहीं, यह बात सही है कि हवा के जोर से पेड़ उखड़ते हैं, हवा के जोर से उगते नहीं, यह बात सही है, लेकिन यह बात भी सही है कि यह हवा जो सुधार की है, tax compliance के सुधार की है, वह अब रुकने वाली नहीं और हो सकता है कि यह "हुदहुद" में भी बदल जाए, तो कोई आश्चर्य नहीं।

उपसभापति महोदय, जब हवा चलती है, तो पत्ते उड़ जाते हैं और जमीन दिख जाती है। जब यह हवा चल रही है, तो पत्ते उड़ रहे हैं, जमीन दिख रही है, बहुत लोग जो छुपे हुए थे, उनकी हकीकत, जमीनी हकीकत अब दिखनी शुरू हुई है। स्वाभाविक है कि एक वग में इस कारण से कुछ बेचैनी होगी।

उपसभापति महोदय, सरकार के लिए गए और कई निर्णयों को देखें, तो संभावित आर्थिक विकास, संतुलित बाजार, उत्पादक युवा शक्ति, जागरुक नागरिक, नये अवसर, नये आयाम इत्यादि के प्रति आत्म विश्वास से लबरेज़ है, विश्वस्त है। किसानों की आमदनी, गरीबों की आधारभूत जरूरतें, दुनिया के साथ आधुनिकता की कदम ताल, संस्थागत मजबूती, राज्यों की सहयोगिता, कर नीतियों में बदलाव इत्यादि बड़े कदम हैं, पर राज्यों के बीच की आर्थिक असमानता को दूर करने की भी बड़ी चुनौती है, जिसकी ओर स्पष्ट कदम उठाए गए हैं।

उपसभापति महोदय, कोई राज्य प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के बावजूद पिछड़ा है, तो यह समस्या सिर्फ उस राज्य की नहीं होनी चाहिए, बल्कि सारे देश की समस्या होनी चाहिए। इसमें कोई शक नहीं कि इन राज्यों को अब कैम्पा फंड, खदानों की नीलामी से होने वाली आय का एक हिस्सा, मिनरल फंड इत्यादि द्वारा कुछ धन मिलना शुरू हुआ है। सदन को यह भी जानकारी होनी चाहिए और अधिकांश लोगों को मालूम है कि इस देश का सबसे गंदा शहर सर्वे में धनबाद को घोषित किया गया। वह धनबाद शहर, जहां पर काला पत्थर, गैंग्स ऑफ वासेपुर फिल्मों की शूटिंग हुई, जिसे देश में "कोयले की राजधानी" के नाम से जाना जाता है।

उपसभापति महोदय, यह सिर्फ धनबाद की बात नहीं है, यह हमारी चिंता की बात है कि जिस जगह ने अपनी छाती से सब कुछ निकाल कर दिया, हमने उसको देश का सबसे गंदा शहर बना कर छोड़ा। यह मैं एक उदाहरण के रूप में दे रहा हूं कि प्राकृतिक संसाधन होने के बावजूद वह उनके लिए वरदान नहीं, बल्कि अभिशाप बन गया है। इसकी चिंता इस सदन को करनी चाहिए। अब इन विसंगतियों को दूर करने का समय आ गया है। झारखंड में मिनरल्स हैं, खदानें हैं, किसी ने अभी कहा कि "यहाँ खुदा है, वहाँ खुदा है, जो आज नहीं खुदा, वह कल खुदेगा।"

उपसभापति महोदय, देश के लिए खोदना है, तो खोदो, पर उनके आस-पास रहने वाले लोगों की चिंता भी करो, केवल खोदो मत। खुदा भी देख रहा होगा कि कहां-कहां खोदूं और कहां-कहां नहीं खोदूं।

उपसभापति महोदय, हमारे जन-नायक प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी जी ने एक बड़ी बात कह दी है कि देश के गरीबों का सपना और मध्यम वर्ग की क्षमता, अगर ये दोनों मिल जाएं, तो इस देश को बदलने से कोई रोक नहीं सकता। इस क्रम में उन्होंने स्वीकार किया कि मध्यम वर्ग को टैक्स का कुछ अधिक बोझ पड़ेगा, इस को भी उन्होंने स्वीकार किया और हम भी इस चीज़ को स्वीकार करते हैं। मध्यम वर्ग के जो टैक्स देने वाले लोग हैं, जो अधिक लोड ले रहे हैं, उनकी भी मैं सरकार के सामने एक बात रखना चाहूंगा, क्योंकि मैं भी उसी वर्ग से आता हूं। मध्यम वर्ग के लोगों की अपेक्षा है कि सरकार यदि उन्हें जमाकर्ता tax collection system का एक अंग समझे... तो उनके लिए भी सरकार अपनी ओर से एक सामाजिक सुरक्षा कवच प्रदान करे, तो इस वर्ग को बहुत अच्छा लगेगा कि सरकार ने हमें भी अपना अंग समझा। हमारे योगदान को भी सरकार स्वीकार कर रही है और इस से उनका सम्मान और उत्साह बढ़ेगा।

[**उपसभाध्यक्ष (तिरुची शिवा)** *पीठासीन हुए*]

महोदय, मैं आपके माध्यम से वित्त मंत्री जी का ध्यान अपने राज्य झारखंड की ओर ले जाना चाहूंगा, जिसे 16 वर्ष पूर्व वाजपेयी जी व आडवाणी जी ने बनाया था। हम जानते हैं कि यह एक छोटा राज्य है, लेकिन चाहे रेलवे के मामले में कहें या टैक्स रेवेन्यू के मामले में कहें, अभी तक हमारी अलग पहचान नहीं हुई है। हमारा छोटा सा राज्य तीन रेलवे जोंस की टेरिटरी में आता है और ये तीनों उसे थोड़ा किनारे कर के रखते हैं यानी वह किसी priority में नहीं आता है। महोदय, आश्चर्य की बात है कि आज 16 वर्ष के बाद भी हमारे यहां जमा हुए आयकर का एक अच्छा-खासा हिस्सा बिहार के खाते में जमा होता है। मैं चाहूंगा कि इन मुद्दों पर केन्द्र सरकार तुरंत कार्यवाही करे। महोदय, अभी माननीय विवेक गुप्ता जी ने राज्यों के रेवेन्यू की बात कही थी। आप जब उन राज्यों के रेवेन्यू की बात करते हैं, तो उन राज्यों की भी चिंता कीजिए जहां उद्योग, कल-कारखाने इन छोटे-छोटे राज्यों में हैं, लेकिन उनके हैड ऑफिस बड़े-बड़े शहरों में हैं। इस तरह इन की गतिविधि का सारा कर, बड़े शहरों में हैड ऑफिस होने के कारण उनके राज्यों में जुड़ता है। महोदय, अभी तक इस संबंध में कोई विवेचना नहीं हुई कि इनका कुछ हिस्सा, जिन राज्यों में वे व्यापार करते हैं, उन्हें भी मिले। इस बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए।

महोदय अभी जी.एस.टी. व और भी कई प्रस्ताव आने वाले हैं। इसलिए हमें एक चीज़ जरूर ध्यान में रखनी चाहिए कि सरकार यदि एक चतुर्थ वर्ग कर्मचारी भी रखती है, तो उसकी कॉस्ट सरकार को 5-6 लाख रुपए जरूर आती है। जो एक छोटा व्यापारी जो दुकान खोलकर अपनी पूंजी लगाकर व्यापार करता है, तो उसे भी कम-से-कम इतनी छूट मिलनी चाहिए कि 5-7 लाख रुपया सालाना वह कमा सके और उससे जो भी उसका मैचिंग टर्न-ओवर हो, उसके करों के दायरे से उसे

[श्री महेश पोद्दार]

मुक्त रखा जाए ताकि अधिक-से-अधिक लोग स्वरोजगार की दिशा में कदम बढ़ाएं। महोदय, tax compliance के कारण व सरकारी अड़चनों के कारण बहुत लोग स्वरोजगार के लिए कदम बढ़ाने में हिचकते हैं। इसके लिए जरूरी है कि उन्हें उन अड़चनों से मुक्त करें ताकि अधिक-से-अधिक लोग स्वरोजगार की दिशा में जाएं।

महोदय, बजट के कुछ आंकड़ों को हम नज़र अंदाज नहीं कर सकते। राज्यों को वर्ष 2016-17 के अनुमानित 3.6 लाख करोड़ की जगह 4.11 लाख करोड़ दिया जा रहा है। पिछले वर्ष की तुलना में पूंजीगत व्यय करीब 25 प्रतिशत अधिक हो रहा है। वहीं बाजार से नेट उधार पहले के 4.25 लाख करोड़ की तुलना में 3.48 लाख करोड़ लेने का प्रस्ताव है। वहीं विदेशी मुद्रा भंडार 361 बिलियन तक पहुंच गया है। महोदय, 2012-17 की पंचवर्षीय योजना में, उसके प्रथम दो वर्षों के आर्थिक प्रबंधन की तस्वीर तत्कालीन वित्त मंत्री जी ने 2013-14 के बजट में दी थी और कहा था कि 2013-14 में current account deficit को finish करने के लिए 75 बिलियन डॉलर्स और अगले साल भी इतनी ही रकम की आवश्यकता होगी। उसमें उन्होंने घाटे का एक कारण कोयले का आयात बताया था। आज स्थिति यह है कि कोयले के निर्यात के बारे में सोच रहे हैं। महोदय, यह एक ऐसा उदाहरण है जिससे हम बहुत कुछ समझ सकते हैं कि कैसे देश आर्थिक प्रगति कर रहा है। महोदय, 2016-17 में वित्तीय राजस्व में पुनरीक्षित बजट घाटा, 3.5 प्रतिशत की जगह जी.डी.पी. का मात्र 3.2 प्रतिशत ही रह गया है। सभी स्वीकार करते हैं कि पिछले ढाई वर्षों में राजस्व प्रशासन system-oriented और अधिक पारदर्शी हो गया है।

महोदय, इस बजट प्रस्ताव में ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक खर्च के प्रावधान किए गए हैं। सब्जियों की खुली बिक्री, दूध की डेयरी की तरफ ध्यान और पंचायतों का सशक्तिकरण इत्यादि अनेक कदम गांवों के जीवन-स्तर को बढ़ाने का हर संभव निश्चय दिखता है।

महोदय, अंत में देश की गहरी जनतांत्रिक व्यवस्था ने कई जन-नायक दिए। उनके हर बड़े और कड़े निर्णय को देश ने स्वीकार किया, उनको जन-समर्थन मिला, क्योंकि उनके निर्णय जनहित में थे और स्वार्थ व संदेह से परे थे। आज भी अपने जन-नायक के, हर भारतीय के जीवन को बेहतर करने के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में माननीय वित्त मंत्री, श्री अरुण जेटली जी ने जो प्रस्ताव दिए हैं, उनमें शायद ही उन्होंने कोई क्षेत्र छोड़ा हो, जिसमें उन्होंने सुधार की बात न की हो या परहेज किया हो। उन्होंने एक बहुत ही अच्छा बजट प्रस्ताव रखा है। महोदय, मैं इसका पुनः समर्थन करता हूं, धन्यवाद।

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Mr. Vice-Chairman, Sir, thank you. I thank hon. Amma, though she is not with us but she is in the hearts of all the people. Success is modern God. In other words, modern God is success. Now, the modern God is our hon. Prime Minister. Everybody is appreciating nationally and internationally for the success he has obtained in the Uttar Pradesh and Uttarakhand polls. Because of his efforts, management skills, providing LPG cylinders without cost, are some of the causes for his resounding success. Newspapers are quoting Jawaharlal Nehru, Indira Gandhi and then hon. Prime Minister, Shri Narendra Modi as successful Prime Ministers. Everybody is

appreciating his management skills. One of the Harvard Psychologists, namely, Howard Gardner has quoted our hon. Prime Minister as a visionary leader. So, in a book written by him....

SHRI JAIRAM RAMESH: There is a change going on.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Please listen to me. Sir, we must admit modern God's success. It is a ground reality. He has won the elections in Uttar Pradesh even without fielding a minority candidate. Uttar Pradesh is the most populous State. You have to appreciate it. That is a good point. It shows his boldness. ...*(Interruptions)*... About 19 per cent of the population consists of Muslims. But the BJP has not fielded any Muslim candidate in the recent polls. ...*(Interruptions)*... I am telling the truth.

I would like to draw the attention of this House to the fact that our young, dynamic and able Deputy General Secretary, Shri T.T.V. Dinakaran was a two time M.P., one term in Lok Sabha and another term in Rajya Sabha, nominated by Amma. He is now the Deputy General Secretary of the AIADMK. He has already congratulated our hon. Prime Minister. I am merely reiterating the statement issued by our hon. Deputy General Secretary. So, our party, the AIADMK has appreciated and congratulated. ...*(Interruptions)*... Please wait. It is already your slogan. AIADMK has congratulated Shri Narendra Modi for his resounding success. Our hon. Amma was also a visionary leader. Even our hon. Amma was a visionary leader. She introduced many welfare measures. It is only because of her welfare measures that she is still alive, in our hearts. She implemented many welfare measures and she has been a pioneer in this sector. She introduced many welfare measures for the upliftment of the poor, for women and all sections of the society. She single-handedly raised the standard of living of the people of Tamil Nadu.

Sir, I would like to draw the kind attention of the hon. Members to article 38 of our Constitution which says, "(i) The State shall strive to promote the welfare of the people by securing and protecting as effectively as it may a social order in which justice, social, economic and political, shall inform all the institutions of the national life; (ii) The State shall, in particular, strive to minimize the inequalities in income and endeavour to eliminate inequalities in status, facilities and opportunities, not only amongst individuals but also amongst groups of people residing in different areas or engaged in different vocations." Also, there is article 39 which says, "The State shall, in particular, direct its policy towards securing (c) that the operation of the economic system does not result in the concentration of wealth and means of production to the common detriment." But, Sir,

[Shri A. Navaneethakrishnan]

according to one of the surveys, in India, 50 per cent of the wealth is concentrated in the hands of 48 wealthy individuals while the remaining 50 per cent of the wealth is with the poor. This means that just 48 individuals own 50 per cent of the wealth of the nation. Fifty per cent of the wealth is under the control, management and ownership of 48 individuals. I believe, these statistics have never been disputed by anybody. So, though Directive Principles of State Policy are not enforceable in a court of law, they are fundamental to the very governance of the nation. It is my humble view that there is a very strong conspiracy by a group of people who have their vested interests in making the poor poorer and keep enriching themselves unjustly. So, in our governance, irrespective of whichever party is in power or in the Opposition, we must take appropriate steps to remove the inequalities in income, inequalities in social status. We are perpetuating the inequalities in income. That is why 48 individuals are controlling almost 50 per cent of the wealth of our nation. The remaining 50 per cent wealth is with the poor. In such a situation, what is to be done?

Now, Sir, I would like to draw the kind attention of this august House to the speech delivered by our hon. Prime Minister after his resounding success in the elections. His idea of a new India is laudable. We welcome it. He said, and I quote, "I am seeing the election results in the five States as foundation for a New India — a New India of the dreams of 65 per cent population of under-35 youths and of uniquely aware women groups;" "... a new India in which the poor are looking for an opportunity to do something, instead of seeking something." So, his endeavour is, a new India, in which the poor are looking for an opportunity to do something, instead of seeking something. It is a good principle; good speech, good stanza. But, how can the Government do it? I would like to know whether the Government is able to provide an opportunity to 35 year old youth. Our country is facing, according to me, subject to correction and approval by this hon. House, major problems. Water scarcity, population explosion, election expenditures, unemployment, indebtedness and 'S' India problem, not Yes, but, alphabet 'S' problem. I will elaborate it. Then, you will understand what I want to say. So, for agricultural economy of our nation, we need water. But, for agriculture, there is no water. The hon. Chief Minister of Tamil Nadu again requesting the Central Government to nationalise the rivers, and also to link the rivers. But, no steps have been taken by the Central Government, and I would humbly submit that no fund has been allotted for linking of rivers. Again, I repeat it that no fund has been allotted to link rivers in India in the Budget. So, I think, it is not an incorrect statement. So, I think, it is a major flaw on the part of the Central Government.

To run the agricultural economy successfully, water is needed. Even for the people, there will be a water war. So, definitely, now, we are having the war between the two States, namely, Karnataka and Tamil Nadu and Kerala, Mullaperiyar, Cauvery Tribunal. It is not implemented by the Central Government. Though a direction has been given, the Cauvery Management Board has not been constituted. Even before the Supreme Court, the Central Government is taking a contrary stand, through the learned Attorney General. So, now, the Central Government did not take appropriate steps to improve the agricultural economy. That is why, I humbly request the Central Government to take appropriate steps, at least, in respect of small rivers. Small rivers may be linked, and in that area, the people will flourish.

I am hailing from Cauvery Delta. We people in those days, we were ourselves surprised that we were the zamindars, landlords, owning vast tracts of land. But, the reality is, now, all the landlords are workers in the textiles mills in Coimbatore and Tirupur. This is the ground reality. And also, for the kind information of this House, we are employing the cheap labourers from north India in Tamil Nadu because many labourers from there are available at cheap cost. In our areas, the labourers are demanding more money. So, we are getting the labourers from north India, and they are all employed in Tamil Nadu. Our Delta region people migrated to KONGU NADU. We call it KONGU NADU, Combatore and Tirupur. They are serving as labourers in the textiles mills. That is the position now, that is the ground reality. Now, the inequality in income is not removed. Now, the Government did not take appropriate steps to improve the economic conditions of the people. Because of the water scarcity, our agricultural economy is also ruined. So, my humble submission would be, the rural India is neglected. Because of the gross negligence on the part of the Central Government, the entire rural India has been ruined.

So, it can't be rehabilitated in the near future. Every village is suffering for want of better health facilities, nutritious food and better employment opportunities. So, they are all migrating to cities like Coimbatore, Chennai, Mumbai and even to foreign countries. But, they are not able to find out good jobs. They are not able to earn decent incomes. I humbly submit to you to have a look at Article 13 and 38 and see the concentration of wealth and means of production, which is now to the detriment of the common good. The detrimental effect has not been prevented by taking preventive steps. No steps have been taken.

[Shri A. Navaneethakrishnan]

Our hon. Prime Minister has allocated a huge amount for the credit in the agricultural sector. We welcome it. But, now, the Indian banking system is ridiculed world-wide because of Non-Performing Assets. No loan is recoverable. Loans are becoming sticky. I would like to draw your kind attention to a fact, but you may consider me as deviating. The Income Tax Department has published a list of persons who have not paid their Income Tax. But, the persons or companies are not traceable. The defaulters of the Income Tax are not traceable. This is our governance! I draw your kind attention to the fact that the Income Tax which is to be paid to the Government, which the Government is entitled to recover, is not paid and not recovered by the Government in spite of publications made in newspapers and all that. But, the persons required to pay the tax are not traceable. They are invisible. This shows our weakness in administration.

Sir, the money allocated to agricultural credit is huge; there is no doubt about that. But, what could be the problem? The more the credit, the more would be the indebtedness of the farmers. Day-in and day-out, all reports—regional, national and international—indicate that the farmers are committing suicide because of their inability to repay the loans. The interest rate is also usurious. One of the surveys says that the private moneylenders are not causing more harm to the agriculturists. It is only the institutional lending mechanism, namely, the nationalized public sector banks, the private banks whose loans alone are causing the death of farmers. The reason is that the rate of interest is usurious. The rate of interest of private moneylenders is not usurious. The survey says that—if I remember correctly; it is subject to correction—once the agricultural credit is increased, the indication is higher the number of farmers' suicides in the near future. That is why I said that. Sir, 'SIndia' denotes what? I may be permitted to explain what stands for the letter 'S'. We are having 'Make in India' and 'Skill India'. Our India is going to be the 'Suicide India'! So, please concentrate on agricultural activities. The rural India is already ruined. So, after 'Skill India' and 'Make in India', it would be 'Suicide India'! *...(Interruptions)...* So, my humble question would be: Are you providing the opportunities to the youth who are aged around 35 years to be something? If so, what are the means? You all might have read about start up problems of Startup companies. A wide publicity has been given about them. Recently, a co-founder of a Startup company, having office at Bengaluru, visited Chennai and advertised a lot and then was not able to pay up the charges. He was then arrested and detained. So, the Startup entities, though there could be much advertisements, there is no proper regulation. There is no proper

funding to the Startup entities. The youth are employed in Startup entities. The latest attraction is Startup companies. The myth also has been exploded. Now our Indian youths cannot be employed in America thanks to newly elected President. By H 1B Visa and all that, he is making very drastic efforts to see that Indian people are evicted from America. My humble submission would be how the Central Government is going to solve the water scarcity problem. Regarding the election expenditure, though the hon. Finance Minister has given some blueprint, but it was criticized by Prof. Rajeev Gowda. My humble submission would be that the Government must educate the voters and all the political parties should also educate the voters. As rightly pointed out by senior leader, hon. Vajpayee, every Member of Parliament is starting his career by filing a false affidavit regarding the election expenditure. We know the ground reality. ₹ 55,000 crores have been spent in the five States. It has been reported in a newspaper. Nobody can be blamed as to why the voters are ready to receive money for casting votes. It is because of their poverty that they are forced to receive money. They are not willingly receiving the money. Even in those days when I was very young, I was seeing a particular party car would come and ask the Secretary of that unit, 'how much money you need?' 'Don't insult me', the secretary would give the reply. 'How much money you need — ₹ 500, ₹ 1000, ₹ 2000 for your expenses? ' 'Don't provide money for electoral expenses in our branch.' That is the attitude of each and every political party. Now, it has totally changed. ...*(Interruptions)*... I don't want to divulge everything. So, the problem is that running a political party is a very costly affair. ...*(Interruptions)*... We must educate our party cadres. ...*(Interruptions)*... You understand it. ...*(Interruptions)*... That is why we must speak the truth. As a parliamentarian, though without revealing the identity, we must speak the truth. There is nothing wrong in it. ...*(Interruptions)*... So, everybody knows the truth. ...*(Interruptions)*... The newspaper is writing it and putting the cost as ₹ 55,000 crores. ...*(Interruptions)*... We don't know, Sir. ...*(Interruptions)*... The problem is that you are giving it to your candidates. ...*(Interruptions)*... Dr. Maitreyan is a non-practicing doctor. That is good. ...*(Interruptions)*... He is a non-practicing doctor. ...*(Interruptions)*... So, my humble submission would be that we must educate the electors, voters properly. My understanding is that indebtedness and 'S' India problem, suicide India problem is the problem of all the problems. I am of the humble view that regarding the agricultural indebtedness, the principle of non-performing assets should not be applicable. You must have a slab of interest.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): How much more time you want?

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Sir, my party is having 15 minutes. ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): : There are two more speakers from your party.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Within five minutes, I will conclude. (*) I understand.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): : I said how much more time you want. ...*(Interruptions)*... Don't dispute the Chair like this. ...*(Interruptions)*... Don't cast aspersions. ...*(Interruptions)*... I am just asking how much more time you want. ...*(Interruptions)*... Don't cast aspersion on the Chair. ...*(Interruptions)*... You have got two more speakers. ...*(Interruptions)*... No intrusion, please. ...*(Interruptions)*... Let him tell. ...*(Interruptions)*... I am asking him how much more time he wants. ...*(Interruptions)*... It is very, very simple, don't complicate it. ...*(Interruptions)*... I asked him how much time he wanted. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): The Chair can. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: If I am beheaded, I don't bother.* ...*(Interruptions)*... * ...*(Interruptions)*...

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): What does he say? ...*(Interruptions)*... It is totally unbecoming. ...*(Interruptions)*...

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN : *

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI TIRUCHI SIVA): This is on record.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Now, my humble submission would be, regarding agricultural credit, subject to correction and approval, I suggest the concept of NPA shall not be made applicable and the slab of interest rate may be fixed. For one year

*Expunged as ordered by the Chair.

there should not be any interest absolutely. For another year it can be one per cent or three per cent depending upon the quantum of loan available to the farmer. Another suggestion would be regarding the quality of education with affordable cost and educational loan must be provided to the students and also NPA concept shall not be made applicable to educational loans. In Tirunelveli, a poor student committed suicide; he availed loan from SBI. It was assigned to the Asset Reconstruction Company, namely Reliance. Only 50 per cent of the outstanding was remitted by the Company and 50 per cent of the loan amount is yet to be remitted to the bank, but the right to recovery was given to Asset Reconstruction Company. These fellows threatened the young boy that he will not get any employment and they will arrest him. The next day he committed suicide. As per Article 12 of our Constitution, SBI loan cannot be assigned to the Asset Reconstruction Company. This is my humble suggestion. Even on earlier occasions I had made it clear. ...*(Time bell rings)*... So, for agricultural loans and educational loans the concept of NPA shall not be made applicable. So, my humble submission would be that the Central Government miserably failed to protect the poor people. And I request the hon. Finance Minister, — this year is the hundredth birth year of our Puratchi ThalaivarM. G. Ramachandran —the Centenary Year of MGR may be celebrated as a Government function and sufficient funds may be allotted for holding functions by the Central Government as well as by the State Government. Also, I would like to make a humble request to our hon. Finance Minister that *Amma Unavagam* is a good concept to feed poor people. ...*(Interruptions)*... You may call it Amma Restaurant or Amma canteen. By whatever name you may call it, it is very successfully run by our State Government. I request our Finance Minister and our hon. Minister of HRD to see that sufficient funds are allotted to the State of Tamil Nadu and support the schemes because every other State is copying the scheme introduced by our hon. Amma and even in Karnataka they have introduced it. Even in Andhra Pradesh also they have introduced it because for ₹ 2 we can have a full meal. So, please come and visit Amma Canteen.

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (SHRI PRAKASH JAVADEKAR): I have visited it.

SHRI A. NAVANEETHAKRISHNAN: Yes, I am thankful to our very brilliant and very large-hearted HRD Minister. He will do the needful. So, I thank the Chair also for being patient and for giving me the opportunity. Thank you.

SHRI JOY ABRAHAM (Kerala): I thank you, Mr. Vice-Chairman, Sir, for giving me this opportunity to speak in this House. I would have congratulated the NDA Government for their resounding victory in Uttar Pradesh and Uttarakhand, but for the undemocratic action in Manipur and Goa. BJP has done a disservice to democracy by using the Governors of Manipur and Goa and there are allegations of horse trading. I have to say that this has reduced the glitter of your victory. It has reduced the glitter of your victory in Uttar Pradesh and Uttarakhand. It is better that some soul-searching is there on the part of BJP. Sir, hon. President, in his Address, has termed this Session of Parliament as historic on two counts – one is advancement of the Budget cycle and the second one is the merger of Railway Budget with General Budget. Regarding advancement of Budget cycle, I would say that it is of no consequence. But, regarding merger of Railway Budget with General Budget, it is the most unfortunate decision. Sir, railways is the most important public sector undertaking in the country. It is the most important public utility service. People expect, at the time of Railway Budget, announcements regarding new trains, new railway lines, electrification, doubling of tracks, new surveys, etc. But, unfortunately, the merger of Railway Budget with General Budget, everything has gone into oblivion. But, I welcome one thing and that is the importance given to safety and security in railways. This is the only consolation. Sir, railway safety is most important, because, now-a-days, we hear about rail accidents every day. Anyway, there is a separate discussion on the working of the Ministry of Railways. So, I leave the matter for now.

Hon. President, in his Address, has given a rosy picture about favourable monsoon, good Kharif crop and better Rabi season. But, unfortunately, there is no mention about drought situation in South India. Sir, we heard hon. Members in the morning from Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh making submissions about drought situation. I regret that there is not even a mention in the Budget about drought situation. Sir, all Southern States, including Kerala, should be given special package to deal with drought situation. That is my submission.

Sir, Kerala leads in the production of cash crops, namely rubber, coffee, tea and spices. But the commodity boards — Rubber Board, Coffee Board, Tea Board and Spices Board — are given a raw deal in this Budget. The Budget Estimates are cut down this year also. There was a drastic cut last year in allocation to all these commodity boards. This has seriously affected the working of the commodity boards. This is most unfortunate. So, I request the hon. Finance Minister to enhance this year's allocation which will help commodity boards to discharge their responsibilities in an effective manner.

Sir, take the case of the Rubber Board. The actual expenditure during 2015-16 was ₹ 201.74 crores. The Budget allocation for 2016-17 was only ₹ 132.75 crores, but the Revised Estimates was ₹ 148.75 crores. But, unfortunately, the Budget allocation during 2017-18 is only ₹140.10 crores. This is against the Department projected allocation of ₹ 250/- crores, but only ₹ 140/- crores have been given. This allocation is inadequate, as there were already pending replanting subsidy liabilities due to the less Budgetary allotment last year.

Now, take the Coffee Board. During 2016-17, the Budget allocation was ₹ 121.54 crores, which is less than 15 per cent of the previous year's allotment. The revised allocation during 2016-17 comes to ₹141.54 crores. But, unfortunately, the allocation for this year is ₹140.10 crores only. Their Department's projected allocation was ₹ 290/- crores. This is too bad and painful. The Research and Development acitivities of the Board have been hit badly. I seek an enhancement in the Budget allocation of the Coffee Board.

Then, again, I come to Tea Board. The Budget allotment for 2015-16 was ₹ 179.46 crores. The Budget allotment for 2016-17 was only ₹ 129.98 crores. The revised allotment for 2016-17 was ₹ 152.15 crores. The Budget Estimates for 2017-18 is ₹ 160/- crores only. Their Department's projection was ₹ 207/- crores. This inadequate outlay for tea development and promotion schemes has adversely affected the rejuvenation and the replantation activities of the Tea Board. I also seek an enhancement in Budget allocations of Tea Board.

Then, comes the Spices Board. The Budget allotment for the Spices Board in 2016-17 was ₹ 70.35 crores. The Revised Estimate was ₹ 80.35 crores. The Budget allocation for 2017-18, unfortunately, is ₹ 82.10 crores. The present allocation will be insufficient to execute the approved schemes as well as for taking up of various programmes for the development of the spices sector. Sir, I, again, urge the Ministry of Finance to provide necessary funds to all these Commodity Boards in Supplementary Grants for meeting their commited expenditure.

Sir, one word regarding Revenue Insurance Scheme for Plantation Crops. There was one Price Stabilisation Fund Scheme started in 2003, which was officially ended in 2013. All these 10 years, these crops got only ₹ 1.53 crores as assistance from the Price Stabilisation Fund. Actually, ₹ 1,011/- crores was there in the Price Stabilisation Fund. Where has the money gone? I had asked a question here and got the answer. I quote: "The Department of Commerce has recently approved the Rubber Insurance Scheme

[Shri Joy Abraham]

for Plantation Crops for protecting growers of plantation crops from the twin risks of weather and price arising from yield loss due to adverse weather parameters, etc. etc., and income loss caused by fall in international/domestic prices. The Price Stabilisation Fund (PSF) Scheme, 2003, was closed on 30.9.2013, and the new scheme is an improved form of the PSF Scheme." So, this new Insurance Scheme is claimed to be an improvement of the old Scheme. There was an outstanding amount of ₹ 1,011/- crores in that Fund. Where is that money? I did not get any answer. This Insurance Scheme was intended to benefit rubber, coffee, tea, spices and tobacco sectors/growers. Unfortunately, though I have asked for the date of commencement of the Scheme, there was no answer. Sir, the most unfortunate thing is that there is a Budget allocation of only ten lakh rupees each for these commodities — for Rubber, ₹ 10 lakh; for Coffee, ₹ 10 lakh; for Spices, ₹10 lakh; and for Tea, ₹ 10 lakh. This has been done while ₹ 1,011 crore is idling in the old Price Stabilization Fund. This is most unfortunate.

Then regarding this Scheme, Kerala is the most important producer of natural rubber. The Government says that this is a pilot project, and they have selected Palakkad district. The major rubber growing-areas of Kottayam, Pathanamthitta, Ernakulam, etc., are avoided. All these districts are avoided and only a small district Palakkad is included. So, my request to the hon. Finance Minister and also to the hon. Commerce Minister is that major rubber-growing areas including Kottayam, Pathanamthitta and Ernakulam districts should be included in this Project. Regarding the commencement of this Project, the Government should take a decision. There was a proposal for a New Rubber Policy. That was pending for the last two-and-a-half years. The Government says that there was a draft. A draft is there, but there is no final word.

(MR. DEPUTY CHAIRMAN *in the Chair)*

Then, Sir, this Government has to regulate the imports of natural rubber. I admit that it has taken a small step. Formally, the import duty was 20 per cent or thirty rupees whichever is less. When the NDA Government came, they have raised the import duty to 25 per cent or thirty rupees, whichever is less. The 'price cap' is the villain. Even though the import duty was raised from 20 per cent to 25 per cent, there is no benefit for the cultivators. Last year, more than five lakh tonnes of rubber was imported, and the import of rubber is going on unabated. The bound rate fixed by WTO for natural rubber is 25 per cent. We should remove that price cap of thirty rupees and fix import duty at 25%.

We may go for the safeguard duty also. There is a provision in the WTO that we can impose safeguard duty. The Government should take the initiative. We have to submit the statistics to convince the WTO partners that to save natural rubber, this safeguard duty should be imposed. That is very important.

Then, regarding the lending rates of Banks, I had asked a question here.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: So, you have to stop in one minute.

SHRI JOY ABRAHAM: Sir, only one minute will do.

My question was, 'Whether the Ministry has directed the RBI to give instructions to the banks to slash their rates of interest on home and vehicle loans dispersed by them.' Sir, I got the answer. The answer was,

'The Reserve Bank of India (RBI) has deregulated the interest rate on advances sanctioned by Scheduled Commercial Banks.' So, the commercial banks are free to charge any rate of interest for the loans advanced by them. And the reason given is, the rate of interest charged by banks to the borrower varies from bank to bank and depends on various factors such as cost of funds, operating costs, tenor premium, business strategy premium, credit risk premium, etc. Banks have the freedom to offer all categories of advances on fixed and floating interest rates. I have put this question in the context of the SBI. The SBI has declared some cuts in their home and vehicle loans, but Government has said that the RBI has deregulated the interest rate on advances sanctioned by scheduled and commercial banks. I request the Finance Minister to look into the matter.

Sir, I would like to repeat my submission that the commodity boards, that is, Rubber Board, Coffee Board, Tea Board and Spices Board, may be given additional allocations for their survival.

Thank you, Sir.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Now, the hon. Minister of External Affairs, Shrimati Sushma Swaraj, would make a statement on the attack on Indian diaspora in the United States. This is a Statement being made on our demand, on their request, and not a *suo motu* statement. Yet, if some of you wish to seek clarifications, I would allow that, but only up to 6.00 p.m. I would allow only four or five clarifications. We will have to adjourn at 6.00 p.m.

DR. T. SUBBARAMI REDDY (Andhra Pradesh): Sir, I may be allowed to seek clarifications because I was the one who had raised this issue first. I have the right to seek clarifications.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: I will allow you too, but the clarifications must be brief. Now, the hon. Minister.

STATEMENT BY MINISTER

Hate crimes against citizens of Indian origin and Indian nationals settled in the United States of America

विदेश मंत्री (श्रीमती सुषमा स्वराज): माननीय उपसभापति जी, 16 मार्च को माननीय सांसद, डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी जी ने अमेरिका में रह रहे भारतीय और भारतीय मूल के लोगों पर हाल ही में हुए हमलों के बारे में एक विषय उठाया था, जिसमें माननीय सांसद श्री पि. भट्टाचार्य, श्री आनन्द भास्कर रापोलू, श्री विवेक के. तन्खा, श्री रणविजय सिंह जूदेव, श्री अली अनवर अंसारी, श्री पी.एल. पुनिया और श्री मोहम्मद अली खान खाहब ने स्वयं को संबद्ध किया था। मैं आपकी अनुमति से इसी विषय पर एक वक्तव्य सदन में रख रही हूँ।

उपसभापति जी, पिछले कुछ सप्ताह के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका में भारतीय नागरिकों तथा भारतीय मूल के लोगों पर हमले की घटनाएँ सरकार के ध्यान में आई हैं।

22 फरवरी को जीपीएस उपकरण निर्माता गार्मीन में कार्यरत 32 वर्षीय भारतीय इंजीनियर श्रीनिवास कुचीभोत्ला को कैन्सस सिटी के उपनगर ओलेथ में स्थित एक भीड़-भाड़ वाले बार में एडम पुरींटोन नामक एक अमेरिकी नागरिक ने गोली मार दी। एक और भारतीय नागरिक, श्री आलोक मदासानी, जो घटनास्थल पर मौजूद थे, भी इस गोलीबारी में घायल हुए। एक अमेरिकी नागरिक, इयन ग्रीलॉट ने हमलावर को रोकने की कोशिश की, तो उस पर भी गोली चलाई गई और वे भी इस घटना में गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों का उपचार किया गया और अब वे अस्पताल से घर आ गए हैं। 16 मार्च की चर्चा में डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी ने कहा था कि अमेरिकी अधिकारी हत्या करने वाले हमलावार की पहचान नहीं कर पाए हैं और न ही यह पता कर पाए हैं कि यह हमला किस कारण से किया गया। उपसभापति जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सांसद को सूचित करना चाहूँगी कि आरोपी की पहचान तुरंत कर ली गई थी। उसका नाम एडम पुरींटोन है और इस घटना के अगले ही दिन पुलिस द्वारा उसे हिरासत में भी ले लिया गया था । इस मामले को फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन (एफ.बी.आई.) ने अपने हाथ में लिया है और वे इसे घृणाजनित अपराध, hate crime मानकर इसकी जाँच कर रहे हैं।